



कमल संदेश
ikf{k d if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

I nL; rk : +91(11) 23005798

Qkx (dk) : +91(11) 23381428

QDI : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकजी स्मृति न्यास, पी.पी-66,
सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

ई-मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा
डॉ. मुकजी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी-36, एफ.
एफ. कॉम्प्लेक्स, झण्डेवाला, नई दिल्ली-55 से मुद्रित करा
के, डॉ. मुकजी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती
मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया।
सम्पादक - प्रभात झा

विषय-सूची

संगठनात्मक गतिविधियां

कोकराझार (असम) में विशाल रैली.....	6
भाजपा-नीत एनडीए ने जीर्णोपचुनावों में 12 में से 7 सीटें.....	7

सरकार की उपलब्धियां

मेक इन इंडिया वीक.....	9
------------------------	---

वैचारिकी

भाजपा के भविष्य से देश का भविष्य जुड़ गया है - अटल बिहारी वाजपेयी.....	12
---	----

श्रद्धांजलि

विनायक दामोदर सावरकर.....	14
---------------------------	----

जेएनयू प्रकरण

देशद्रोही गतिविधियों को सहन नहीं किया जा सकता.....	15
क्या यही है कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति की नई परिभाषा ? -अमित शाह.....	16
वामपंथी अतिवाद से देशविरोधी ताकतें मजबूत -डा. शिव शक्ति बक्सी.....	17

लेख

मनमोहन सिंह को अपनी पार्टी को क्या नसीहत देनी चाहिए ? - अरुण जेटली.....	19
--	----

अन्य

राष्ट्रपति अभिभाषण.....	20
फसल बीमा योजना के लिए संचालनगत दिशा-निर्देशों का अनावरण.....	25
राष्ट्रीय रूबरु मिशन का शुभारंभ.....	27
विदेशी पर्यटकों के आगमन में 6.8 फीसदी का इजाफा.....	28

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को





सोशल मीडिया से...



श्री अमित शाह

वोट बैंक की राजनीति के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी निम्न स्तर की राजनीति पर आ गए हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी स्पष्ट करें, आजादी के नाम पर देश तोड़ने वाले नारों के साथ हैं या नहीं। अगर नहीं हैं तो उनकी निंदा करें।

श्री राजनाथ सिंह

भारत एक महान लोकतंत्र है जो हर किसी के लिए अवसर प्रदान करता है। समाज के हर वर्ग को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान देना चाहिए। यदि वामपंथी अतिवादी हथियार छोड़ते हैं और हिंसा से दूर रहते हैं तो सरकार संवैधानिक ढांचे के भीतर उन लोगों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। मैं वामपंथी अतिवादियों से अपील करता हूँ कि वे पूरी तरह से हिंसा छोड़ दें और देश की मुख्यधारा में शामिल हो जाएं।

श्री थावरचंद गहलोट

भारत सरकार ने दीक्षा भूमि नागपुर के जीर्णोद्धार हेतु 9,41,39,276 रुपए स्वीकृत किए। समिति को स्वीकृति पत्र सौंपा।

श्री नरेंद्र मोदी @narendramodi

फसल बीमा योजना किसानों की कई समस्याओं का समाधान है। इस योजना के द्वारा हम किसानों का फसल बीमा से टूटा हुआ विश्वास जीतना चाह रहे हैं।

श्री अरुण जेटली @arunjaitley

मीडिया को रिपोर्ट करने का निर्बाध अधिकार है। मीडियाकर्मियों पर हमला अनुचित और निंदनीय है।

श्री रविशंकर प्रसाद @rsprasad

जेएनयू में आतंकवादी अफजल गुरु के लिए शोक सभा हुई, लेकिन पूर्व छात्र कैप्टन पवन, जिन्होंने भारत के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, के लिए कोई एकजुटता नहीं, क्यों?

पाथेय

गणतंत्र की रक्षा

हमें जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यवस्थायें निर्माण करना हैं, उसमें हर एक नागरिक का गौरवपूर्ण स्थान होना आवश्यक है, इसे ध्यान में रखते हुये हमें सारी व्यवस्थायें निर्माण करनी होंगी। संस्थाएं भी उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो, ऐसा होना चाहिए। यह सारी गतिविधियां और हमारे कार्यक्रम इसी दिशा में हमें बढ़ाने वाले हो। संगठन का निर्माण और उसके लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम का क्रियान्वयन-यह है आज की चुनाती। संगठन के सामने एक और कार्य है। हमें अपने आधार का और विस्तार करना है और अन्य अनेक वर्गों के पास पहुंचना है। यह हमारा अथक प्रयास रहना चाहिए। हमारे लिए यह चुनौती है और हमें इस चुनौती का मुकाबला करना है और सफल होकर बाहर आना है। हमें देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अपने संगठन को मजबूत करना है और इस प्रकार समाज के सभी वर्गों के लोगों को निरन्तर अधिकाधिक अपने पक्ष में करना है। हमारे एजेण्डा में यह कार्य सर्वोपरि होना चाहिए।

- कुशाभाऊ ठाकरे



संसद की कार्यवाही में बाधा लोकतंत्र के हित में नहीं

सं सद का बजट सत्र राष्ट्रपति अभिभाषण से शुरू हुआ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश की भावना को सटीक शब्दों में व्यक्त किया और कहा कि लोग संसद को राष्ट्रहित में कार्य करने की अपेक्षा रखते हैं। संसद लोकतंत्र का मंदिर है और यह सफलतापूर्वक कार्य करे। इसका दायित्व सभी राजनैतिक दल एवं संसद सदस्यों के ऊपर है। पिछले सत्र का अनुभव अब भी लोगों के मन में ताजा है, जब कांग्रेस ने किसी न किसी बहाने संसद की कार्यवाही बाधित किया तथा न केवल राष्ट्रहित के कई पहलों को रोका, बल्कि कई महत्वपूर्ण विधेयक इस अड़ंगेबाजी की भेंट चढ़ गए। हमारे संसदीय लोकतंत्र में मतभिन्नता का हमेशा स्वागत हुआ है लेकिन यह मतभिन्नता इतनी दूर तक भी नहीं जानी चाहिए कि लोकतंत्र का चल पाना मुश्किल हो जाय। लोकतंत्र का सार इसमें है कि अपने मतभेद दूर कर आगे बढ़ें और जो ऐसा नहीं करते, जनता जो कि लोकतंत्र में सर्वोच्च है, उन्हें सबक सिखाती है। संसद के सदस्यगण एवं राजनैतिक दल राष्ट्रपति के द्वारा उठाये गये प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर संसद में स्वस्थ एवं सकारात्मक चर्चा के लिये एकजुट हों।

भाजपा-नीत राजग सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र के आधार पर देश के सर्वांगीण विकास के लिये कृतसंकल्प है। कई अभिनव पहल हुए हैं जिसके परिणाम अब आने लगे हैं। सरकार गरीबों, के विकास, किसानों की समृद्धि एवं युवाओं के रोजगार के लिये प्रतिबद्ध है। गरीबी हटाने तथा सामाजिक सुरक्षा की कई योजनायें चल रही हैं।

वित्तीय समावेशी योजना 'जन धन योजना' के परिणाम निकल रहे हैं और प्रत्यक्ष लाभान्तरण योजना को अनेक सरकारी योजनाओं तक विस्तारित किया गया है। लगभग सभी क्षेत्रों में तेजी से अनुकरणीय परिवर्तन हो रहा है। हर मोर्चे पर तेजी से विकास की गति नजर आ रही है और भारत के लोगों के लिए आशाओं की नई उम्मीदें जाग उठी हैं। जिन किसानों को 'More crop, per drop' और फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं से लाभ मिल रहा है, वे कृषि के उच्च तरीके अपनाने का साहस कर रहे हैं। मेक इन इण्डिया, स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा, स्किल इण्डिया आदि योजनाओं ने हमारे युवा लोगों में नई आशाएं पैदा की हैं जिनके लिए अब भारी अवसर दिखाई पड़ रहे हैं और वे योजनाओं के अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न मोर्चों पर लिए गए साहसी कदमों के कारण विदेशी राष्ट्रों के साथ गठबंधन होने से भारत की नई छवि उभरी है और विश्व भर के लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी आस्था प्रगट कर रहे हैं। हर जगह सकारात्मक माहौल दिखाई पड़ रहा और देश प्रगति की राह पर चलता दिखाई पड़ रहा है।

संसद भारत के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। संसद में बहस-मुबाहिसा हमारे लोकतंत्र की ताकत तथा हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों की आस्था का प्रतीक है। हमारे लोकतंत्र की सफलता के लिए इसका सफल कार्यान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसद लोगों की आकांक्षाओं का परम प्रतीक है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ठीक ही कहा है कि लोकतांत्रिक स्वभाव में बहस-मुबाहिसा आवश्यक है, न कि बाधाएं या व्यवधान पैदा किए जाएं। भारत में व्यवधान कभी स्वीकार नहीं किए गए हैं और जो लोग इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, उन्हें भारत के लोगों ने नकारा ही है। जहां सरकार संसदीय कार्य सुचारू और रचनात्मक ढंग से करने का निरन्तर प्रयास कर रही है, वहीं विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस इसके लिए कई अवसरों पर अपना रूख रखने में असफल रही है।

इस बार कांग्रेस को सुधारात्मक उपाए अपनाने चाहिए, क्योंकि बजट सत्र राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे सुनिश्चित करना चाहिए, देश आगे बढ़ता रहे और संसद लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार कामकाज कर सके। ■

संगठनात्मक गतिविधियां : कोकराझार (असम) में विशाल रैली

“जनता के कल्याण के बजाय अपना तिजोरी भरने का काम कर रही है कांग्रेस सरकार”

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 14वें बोडोलैंड दिवस के अवसर पर असम के कोकराझार में एक विशाल रैली को संबोधित किया और असम की जनता से राज्य की भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ कर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत और विकसित असम के नवनिर्माण का आह्वान किया। इसके बाद उन्होंने नगांव में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मलेन को सम्बोधित किया और कार्यकर्ताओं से असम में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की अपील की। कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है तो असम को भी कांग्रेस मुक्त करना होगा।



भाजपा अध्यक्ष ने 10 फरवरी को असम और बोडोलैंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन की संज्ञा देते हुए कहा कि आज ही के दिन 10 फरवरी, 2003 को बोडोलैंड आंदोलन का सुखद समाधान हुआ था। उन्होंने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि अटल जी और आडवाणी जी के समय बोडोलैंड के शांति और विकास के लिए किया गया समझौता आज हिंसा के रास्ते को छोड़ कर विकास के पथ पर तीव्र गति से गतिशील है तथा आज बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट असम और बोडोलैंड के विकास के लिए देश की मुख्यधारा से कंधे-से-कंधा मिलाकर काम कर रही है। श्री शाह ने कहा कि इसलिए आने वाले असम

विधान सभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, “मैं बोडोलैंड की जनता को आश्चस्त करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट की एक हजार करोड़ रुपये की राशि की मांग से अधिक ही देगी ताकि बोडोलैंड

सहित पूरे असम का विकास देश के अन्य विकसित राज्यों की तरह ही एक समान रूप से हो सके।” श्री शाह ने कहा कि बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के साथ यह गठबंधन कोई राजनीतिक समझौता नहीं है, बल्कि यह असम के विकास व उसके बेहतर भविष्य के लिए किया गया एक विकास का समझौता है।

असम में कांग्रेस के 15 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोलते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि असम बीते 15 सालों में विकास के दौर में पिछड़ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार और उनकी सत्ता में किसी भी तरह बने रहने की लालसा ने असम को बर्बाद करके रख

दिया है। उन्होंने कहा कि भरपूर प्राकृतिक संसाधन, मेहनतकश युवाओं की अदम्य ऊर्जा और राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाओं के बावजूद आज असम काफी पीछे है। उन्होंने कहा कि आजादी के समय जहाँ असम देश का 5वां सबसे खुशहाल राज्य था, वहीं अब असम गरीब राज्यों की सूची में काफी निचले पायदान पर आ गया है। श्री शाह ने कहा कि 1962 में चीन के साथ हो रही जंग के बीच एक समय तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भी असम को अलविदा कह दिया था लेकिन देश के जांबाज सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर असम की रक्षा की।

कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति पर निशाना साधते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति की देन है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में भाजपा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट की सरकार बनती है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को पीछे धकेला जाएगा, घुसपैठियों का प्रवेश पूरी तरह से रोका जाएगा और असम एवं बोडोलैंड के युवाओं के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

श्री शाह ने कहा कि असम में माता मृत्यु दर देश में सर्वाधिक है, महिलाओं पर बीते एक साल में हजारों अत्याचार की घटनाएं हुई हैं। श्री शाह ने जोर देते हुए कहा कि जिस राज्य में महिलायें सुरक्षित नहीं हो, एक करोड़ से ज्यादा की आबादी गरीबी रेखा से नीचे

संगठनात्मक गतिविधि : उप-चुनाव परिणाम

भाजपा-नीत एनडीए ने जीतीं उपचुनावों में 12 में से 7 सीटें

हाल के उप-चुनावों में आठ राज्यों में हुए 12 सीटों में से भाजपा ने चार सीटें तथा उसके अन्य एनडीए सहयोगियों ने तीन सीटें जीतीं। उत्तर प्रदेश में शासित समाजवादी पार्टी की हालत सबसे खराब रही। एसपी ने उत्तर प्रदेश में हुए तीन सीटों में से दो सीटें गंवा दी जिसमें से एक-एक सीट भाजपा और कांग्रेस के खाते में गई। भाजपा ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक में एक-एक सीट पर कब्जा कर लिया।

भाजपा मलिहार (मध्य प्रदेश), मुजफ्फर नगर (उत्तर प्रदेश) और कर्नाटक में हेब्बल और देवदुर्गा में विजेता रही:

बिहार में एनडीए सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (आरएलएसपी) पर कब्जा जमाए रखा। शिवसेना ने महाराष्ट्र में पालकड सीट जीती, पंजाब में खरूर साहब निर्वाचन क्षेत्र से अकाली दल को विजय मिली और सत्ताधारी टीआरएस ने तेलंगाना में न्यायखंड में कांग्रेस को करारी मात दी।

भाजपा शासित मध्य प्रदेश में श्री नारायण त्रिपाठी ने कांग्रेस से 27000 वोटों से अधिक प्राप्त कर मलिहार निर्वाचन क्षेत्र छीन लिया। उन्होंने भाजपा में शामिल होने के बाद सदन छोड़ दिया था। भाजपा के श्री कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर से निर्वाचित घोषित हुए। उन्होंने एसपी के चित्तरंजन स्वरूप को लगभग 6000 वोटों से पराजित किया।

आरक्षित देवदुर्गा निर्वाचन क्षेत्र (रायपुर जिला) कर्नाटक में भाजपा के श्री के. शिवाना गौड़ा नायक ने 16871 वोटों से सीट जीत कर कांग्रेस के ए. राजशेखर को पराजित किया।

बिदर में भाजपा दूसरे स्थान पर रही। कर्नाटक के सभी तीनों स्थानों पर जनता दल (सेक्युलर) की हालत सबसे खराब रही और वह तीसरे स्थान पर रही।

बिहार में आरएलएसपी के सुधांशु शेखर हरलाखी से निर्वाचित घोषित हुए और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार मौहम्मद शब्बीर को 18000 वोटों से पराजित किया। नवम्बर 2015 में नई बिहार विधान सभा में शपथ ग्रहण समारोह ने कुछ घण्टे पूर्व ही आरएलएसपी विधायक बसंत कुमार कुशवाहा की मृत्यु के कारण यह चुनाव कराना आवश्यक हो गया था। सुधांशु शेखर कुशवाहा के सुपुत्र हैं।

भाजपा त्रिपुरा में दूसरे स्थान पर रही

त्रिपुरा की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्सवादी) ने अमरपुर पर कब्जा बनाए रखा, जबकि भाजपा ने कांग्रेस को पिछले स्थान पर धकेल दिया जिससे राज्य में कांग्रेस के हास का संकेत मिलता है।

सीपीआई(एम) के परिमल देबनाथ ने भाजपा के रणजीत दास को 10597 वोटों से हराया, जबकि कांग्रेस के चंचल डे को केवल 1231 वोट मिले और चौथे स्थान पर रहे। त्रिपुरा के राजकीय पीपुल फ्रंट को 1623 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रखा।

लोगों ने विकास की राजनीति पर भरोसा रखा

देश भर में भाजपा-नीत एनडीए की चुनावी विजय के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इससे पता चलता है कि लोग विकास की राजनीति में विश्वास रखते हैं।

उन्होंने ट्वीट कर बताया कि यह देख कर खुशी होती है कि भाजपा और उसके सहयोगियों कि देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और केन्द्रीय भागों में विजय हुई। मैं लोगों के प्रति अपना आभार प्रगट करता हूँ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए का यह प्रयास सराहनीय है। भारत में सभी लोगों में विकास और सिर्फ विकास की राजनीति पर भरोसा किया है।

कांग्रेस और उसके सहयोगियों की नकारात्मक राजनीति के खिलाफ जनादेश है।

भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने हाल के उप-चुनावों 12 में से 7 सीटें जीतीं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने इस विजय की सराहना करते हुए कहा कि लोग विपक्ष की 'वोट बैंक' की राजनीति की अपेक्षा 'विकास की राजनीति' को बेहतर समझते हैं।

श्री शाह ने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं वोट बैंक की राजनीति की अपेक्षा विकास की राजनीति पर विश्वास करने पर लोगों की सराहना करता हूँ। मैं अपने कार्यकर्ताओं, भाजपा राज्य इकाईयों तथा उपचुनावों में प्रभावी परफोर्मेंस के लिए बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की 'नकारात्मक राजनीति' के खिलाफ जनादेश

है। लोग उन्हें यह सबक निरन्तर सिखाते रहेंगे।’

बिहार, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एनडीए सहयोगी दलों, भाजपा कार्यकर्ताओं, संगठनात्मक अधिकारियों, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यों के लोगों की इस अनुकरणीय सफलता के लिए बधाई। भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि यह विकास नीति की विजय है। यह ‘सबका साथ, सबका विकास’ और भाजपा के सुशासन की विजय है।

भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि यह इस प्रकार के निराधार प्रचार के खिलाफ जनादेश है। जिससे संसद के कार्य में बाधा डालकर सरकारी विकास कार्यों में बाधा न डालने का संकेत मिलता है और लोगों ने इस विजय से दिखा दिया है कि वे ऐसे विकास विरोधी ग्रुपों की वास्तविक सच्चाई को सामने ला दिया है।

श्री शाह ने कहा कि देश के विकास में बाधा डालने की नकारात्मक प्रवृत्ति के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। लोग कांग्रेस और उनके सहयोगियों की आर्थिक प्रगति की नकारात्मक प्रवृत्ति के खिलाफ आक्रोशित हैं और वे आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार आचरण करते रहेंगे।

भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि लोगों के कांग्रेस के निराधार आरोपों को निरर्थक कर दिया है और उन्होंने

भाजपा के सुशासन एवं विकास के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि जो लोग गरीब-विरोधी, विकासात्मक नकारात्मक राजनीति की विचार लेकर चलते हैं, उन्हें गम्भीर रूप से आत्म-निरीक्षण करने की जरूरत है।

भाजपा ने गाजियाबाद नगर निगम मेयर का पद जीता

भारतीय जनता पार्टी ने गाजियाबाद नगर निगम, उत्तर प्रदेश में 16 फरवरी 2016 को हुए उप चुनाव में मेयर का पद प्राप्त कर लिया है। भाजपा प्रत्याशी श्री अंशु वर्मा को जीएमसी पद का मेयर पद मिल गया। उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुधान रावत और कांग्रेस के लालमन सिंह को पराजित किया। अगस्त 2015 में तेलुराम कम्बोज के पद पर मेयर की मृत्यु के बाद यह उप-चुनाव कराना आवश्यक हो गया था।

इस चुनाव में 12 प्रत्याशी ने परन्तु मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच था। स्व. तेलुराम कम्बोज को समाजवादी पार्टी के निकटतम प्रतिद्वन्दी को पराजित कर वर्ष 2012 को मेयर निर्वाचित किया गया है।

ध्यान देने की बात है कि भाजपा के अंशु वर्मा ने समाजवादी पार्टी के सुदन रावल को 45228 वोटों से मेयर के उप-चुनाव में पराजित किया है। ■

पृष्ठ 6 का शेष...

गुजर-बसर करने को मजबूर हो, लगभग आधी आबादी पीने योग्य पाने से मरहूम हो, ब्रह्मपुत्र जैसी पवित्र नदी होने के बावजूद लगभग तीन चौथाई से अधिक किसानों के पास सिंचाई की सुविधा न हो, एक तिहाई से अधिक आबादी के पास बिजली न हो, लगभग 23 लाख से अधिक बेरोजगार हों, उस राज्य में कांग्रेस से विकास की आशा कैसे की जा सकती है जबकि आजादी के बाद से प्रदेश में अधिकतर कांग्रेस और उनके सहयोगियों का ही शासन रहा है। श्री शाह ने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि यदि असम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, असम में रेलमार्गों, सड़कों का जाल बिछाना है, इसे देश के अन्य विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है तो प्रदेश में भाजपा - बोडोलैंड गठबंधन की सरकार बनानी होगी। कैंग की 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये के घोटाले रिपोर्ट का हवाला देते हुए श्री शाह ने कहा कि असम सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और प्रदेश की जनता के कल्याण के बजाय अपना तिजोरी भरने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों देश में पिछली कांग्रेस सरकार के समय लगातार 10 वर्षों तक असम से ही प्रधानमंत्री रहने के बावजूद असम विकास के दौर में पिछड़ता ही चला गया।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने असम की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि असम की जनता आज के दिन असम को सुख, शांति और समृद्धि के रास्ते पर ले चलने के लिए कृतसंकल्प होने का निर्णय ले। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि असम के विकास के लिए आप भाजपा को एक मौका दें और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम असम को देश के अन्य विकसित राज्यों के कतार में खड़ा कर यहां की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। साथ ही श्री शाह ने कार्यकर्ताओं से राज्य में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए एकजुट हो जाने का आह्वान किया। ■

सरकार की उपलब्धियां : मेक इन इंडिया वीक

15 लाख करोड़ के निवेश समझौते मिलेंगी 30 लाख नौकरियां

मुंबई में 13 फरवरी से प्रारम्भ हुआ देश का प्रथम मेक इन इंडिया सप्ताह काफी सफल रहा। इस कार्यक्रम के दौरान 15.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और इस सम्मेलन से दुनिया भर के निवेशकों के बीच भारत के बारे में एक अनुकूल माहौल बनने में मदद मिली। इन समझौतों से करीब 30 लाख नौकरियां मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

मुं बई में आयोजित देश के पहले मेक इन इंडिया सप्ताह ने कामयाबी की नई इबारत लिखी है। इस सप्ताह के दौरान 15.2 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर दस्तखत किए गए। इस कार्यक्रम के जरिये भारत ने निवेश के मामले में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाबी हासिल की। सरकार ने भरोसा जताया है कि इन निवेश की वजह से लगभग 30 लाख रोजगार पैदा होंगे। देश को दुनिया का सबसे बड़ा मैनुफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में दुनिया के 102 देशों और देश के 18 राज्यों ने हिस्सा लिया। करीब 9000 भारतीय कंपनियों ने इसमें शिरकत की। इस सप्ताह के अंत में 15.2 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर दस्तखत किए गए। इनमें से करीब 8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव महाराष्ट्र के हिस्से में आए। डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल, एग्री, फूड प्रोसेसिंग, टेलीकॉम, ऑटो सहित लगभग सभी सेक्टरों में निवेश के प्रस्ताव पर दस्तखत हुए। इस पूरे सप्ताह के दौरान करीब 9 लाख लोग यहां लगाई गई प्रदर्शनी देखने आए जो अपने आप में रिकॉर्ड है।

महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि खुद उसे भी इतने अच्छे रिस्पॉंस की

उम्मीद नहीं थी। करीब डेढ़ लाख के निवेश प्रस्ताव विदर्भ और मराठवाड़ा के ग्रामीण और पिछड़े इलाके के लिए हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी करीब 10



हजार करोड़ का निवेश करने पर सहमति बन गई है। लघु उद्योगों में इतने बड़े पैमाने पर निवेश होने से छोटे उद्योगपतियों को काफी फायदा होगा। निवेशकों को लुभाने के लिए कई जटिल पॉलिसियों को रद्द कर नई पॉलिसी बनाई गई हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस के जरिए उद्यमियों की परेशानियों को कम करने की कोशिश की गई है।

युवाओं के लिए रोजगार और स्व-रोजगार का अवसर है 'मेक इन इंडिया': मोदी

मुंबई में मेक इन इंडिया सप्ताह के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को कहा कि हमने युवाओं के लिए रोजगार जुटाने

और स्व-रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की है। हम भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में

जोरदार तरीके से काम कर रहे हैं। हम अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण का हिस्सा निकट भविष्य में 25 प्रतिशत तक करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि हम दुनिया के सामने भारत में विनिर्माण डिजाइन, अनुसंधान और विकास के लिए आधार के रूप में मौजूद बड़े अवसरों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत शायद एफडीआई के लिए सबसे अच्छा देश है। अधिकांश एफडीआई क्षेत्रों को स्वतः मंजूरी के मार्ग पर डाल दिया गया है। मेरी सरकार द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से हमारा एफडीआई प्रवाह बढ़कर 48 प्रतिशत हो गया है। वास्तव में, दिसंबर,

2015 में एफडीआई प्रवाह देश में सबसे अधिक था। ऐसा उस समय हो रहा है जब वैश्विक एफडीआई में भारी गिरावट हो रही है। हमने कराधान मोर्चे पर भी अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं। हमने कहा है कि हम पूर्वव्यापी कराधान का आश्रय नहीं लेंगे। हम अपनी कर व्यवस्था को पारदर्शी, स्थिर और पूर्व अनुमान योग्य बनाने की ओर भी तेजी से कार्य कर रहे हैं। हमने कारोबार को आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। विनिर्माण क्षेत्र में प्रक्रियाओं को सरल बनाने और प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। इन प्रयासों में लाइसेंसिंग, सीमा पार से व्यापार, सुरक्षा और पर्यावरण मंजूरी भी शामिल हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ा सहित अनेक क्षेत्रों में आकर्षक योजनाओं की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने रक्षा क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण नीति सुधार किए हैं। हमने रक्षा उद्योग को वह सब दिया है जिसकी वह मांग कर रहा था। एक अन्य उदाहरण प्राकृतिक संसाधनों का सरल और पारदर्शी आवंटन है। इसके दोहरे लाभ हैं। एक ओर ऐसे संसाधनों का उत्पादन बढ़ गया है और दूसरी ओर हमने पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की है जो उपयोगकर्ता और हितधारकों को समान अवसर उपलब्ध करा रही है। इस वर्ष देश में कोयले का सर्वोच्च रिकार्ड उत्पादन होगा। वर्ष 2015 के दौरान देश में सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन हुआ था।

श्री मोदी ने कहा कि संपत्तियों और अधिकारों की सुरक्षा के मुद्दों पर हमने पहले ही मध्यस्थता कार्यवाही को तेजी से निपटाने के लिए कानून बनाया है। हम उच्च न्यायालयों में समर्पित वाणिज्यिक अदालतों और वाणिज्यिक

प्रधानमंत्री के संबोधन की मुख्य बातें

- ▶ संयुक्त पीएमआई उत्पादन सूचकांक जनवरी, 2016 में उछल कर 11 महीनों के उच्च स्तर 53.3 प्रतिशत पर पहुंच गया है।
- ▶ पिछले 8 महीनों के दौरान निवेश प्रस्तावों की कुल संख्या में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
- ▶ 2015 में हमने मोटर वाहनों का अब तक का सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया है।
- ▶ पिछले 10 महीनों के दौरान देश में 50 नई मोबाइल फ़ैक्ट्रियों की स्थापना हुई है।
- ▶ इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग 6 गुनी बढ़कर 18 मिलियन तक पहुंच गई है।
- ▶ ईएसडीएम इकाइयों के नाम से विख्यात 159 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों की 2015 में स्थापना हुई।
- ▶ कुछ विशेष एजेंसियों के अनुमान के अनुसार भारतीय रोजगार बाजार एक मजबूत धरातल पर है। उदाहरण के लिए, भारत के मॉस्टर रोजगार सूचकांक जनवरी, 2016 में 229 रहा जो कि पिछले वर्ष जनवरी की तुलना में 52 प्रतिशत अधिक है।

प्रभागों की स्थापना कर रहे हैं। कंपनी कानून न्यायाधिकरण का गठन अंतिम चरण में है। हम जल्दी ही एक प्रभावी आईपीआर और पेटेंट व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। हमें दिवालियापन कानून पास होने की उम्मीद है जिसे संसद के पटल पर रखा गया है। नीति और प्रक्रिया के बारे में हमने अपनी प्रणालियों को साफ, आसान, सक्रिय और व्यापार के अनुकूल बनाया है।

उन्होंने कहा कि मैं न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन में विश्वास करता हूँ। इसलिए हम निवेश और विकास को प्रभावित करने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हो रहे परिवर्तनों और सुधारों को न केवल संघीय सरकार के स्तर पर देखना अच्छा लगता है, बल्कि राज्य स्तर पर भी इससे खुशी मिलती है।

भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। इस वित्तीय वर्ष के अंत में देश में जीडीपी की वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक होगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, ओईसीडी, एशियाई विकास बैंक तथा अन्य संस्थानों में आने वाले दिनों में और बेहतर विकास दर का अनुमान लगाया है। 2014-15 में भारत ने वैश्विक विकास में 12.5 प्रतिशत योगदान दिया है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अपने हिस्से की तुलना में भारत का वैश्विक विकास में 68 प्रतिशत अधिक योगदान है। उन्होंने कहा कि भारत को अनेक वैश्विक एजेंसियों और संस्थानों ने सबसे आकर्षक निवेश स्थान का दर्जा दिया है। व्यापार को सरल बनाने के मामले में विश्व बैंक द्वारा तैयार नवीनतम वैश्विक रैंकिंग में भारत ने 12 रैंक ऊपर पहुंच गया है। भारत ने निवेश आकर्षित करने के मामले में अपनी अंकटाड रैंकिंग सुधार कर 15वीं से 9वीं कर ली है। भारत ने विश्व आर्थिक फोरम के वैश्विक आर्थिक सूचकांक पर 16 अंकों का सुधार किया है। मूडी 'ज' ने भी भारत की रैंकिंग को अपग्रेड कर सकारात्मक कर दिया है।

स्वीडन, फिनलैंड एवं पोलैंड के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुंबई में 13 फरवरी को मेक इन इंडिया सेंटर प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद

के साथ अपनी बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इंजीनियरिंग, बिजली संयंत्रों, बायोटेक एवं अन्वेषण में फिनलैंड की सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। प्रौद्योगिकी का

प्रधानमंत्री ने बम्बई आर्ट सोसायटी के नए भवन का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 फरवरी को बम्बई आर्ट सोसायटी के नए भवन परिसर की उद्घाटन संबंधी पट्टिका का अनावरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि शायद ही कोई ऐसा संस्थान हो जो तीन दशकों तक अपना प्रभाव छोड़ता हो, लेकिन बम्बई आर्ट सोसायटी ऐसा करने में कामयाब रही है। इस सोसायटी की स्थापना 19वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। इसका कारण यह है कि कला की अपनी शक्ति और संदेश होते हैं।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि कला सिर्फ दीवारों का अलंकरण मात्र ही नहीं है, बल्कि समाज की शक्ति का स्तंभ होती है। उन्होंने कहा कि कला बच्चों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि इस मशीनी युग में भी कला व्यक्तियों में मानवता की भावना को जिंदा रखने में मदद करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कला को कभी भी अपने संस्थापन पर निर्भर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे निश्चित रूप से संस्थापन द्वारा संरक्षण दिया जाना चाहिए।

कला के तीन शब्दों ए, आर, और टी, पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शब्द चिरायुता, जातिहीनता व क्षेत्रहीनता और शाश्वतता जैसे गुणों का बखान करते हैं और कला को परिभाषित करते हैं। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया है कि कलाकृति के सृजन की प्रक्रिया का प्रलेखन करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है जिससे लोगों को कलाकार के विचारों की प्रक्रिया को समझने में मदद मिल सकती है। ■

प्रधानमंत्री की उपस्थिति में मेक इन इंडिया केंद्र के उद्घाटन के साथ-साथ समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान

- ▶ ट्विन स्टार (स्टरलाइट होल्डिंग कंपनी है) और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, जो ताइवान से तकनीकी भागीदार ऑट्टान के साथ एलसीडी फैंब में निवेश कर रही है, के बीच समझौता ज्ञापन। यह भारत में अपने किस्म की पहली परियोजना होगी। इस परियोजना पर प्रस्तावित निवेश 20000 करोड़ रुपए होगा।
- ▶ मैसर्स हिंदुस्तान कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, जैन इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड और महाराष्ट्र सरकार के कृषि एवं विपणन विभाग के मध्य विदर्भ के संतरा उत्पादन करने वाले किसानों की मदद के लिए एक जूस उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन। इस परियोजना का उद्देश्य संतरा उत्पादकों को उनकी फसल का अधिक मूल्य दिलाना और लाभदायक रोजगार जुटाना है। इस परियोजना से 2 एकड़ तक की औसत जोत वाले 5000 किसानों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है।
- ▶ मैसर्स रेमंड इंडस्ट्रीज और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के मध्य 'फार्म टू फ़ैब्रिक' पहल के हिस्से के रूप में समझौता ज्ञापन। रेमंड लिलेन यार्न और फ़ैब्रिक तथा परिधानों के विनिर्माण के लिए 1400 करोड़ रुपए निवेश करना चाहता है। यह इकाई अमरावती जिले के नंदगांव टेक्सटाइल पार्क में स्थापित की जाएगी जो इस जिले और विदर्भ क्षेत्र के किसानों से कपास की खरीदारी करेगी। यह क्षेत्र किसानों द्वारा आत्महत्या करने और किसानों की बदहाली से प्रभावित है।

स्वीडन एवं फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों एवं पोलैंड के उपप्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं कीं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री श्री स्टीफन लॉफवेन के साथ अपनी बातचीत में मेक इन इंडिया पहल के तहत एक उल्लेखनीय भागीदार के रूप में स्वीडन की सराहना की। उन्होंने प्रतिरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, चिकित्सा उपकरण आदि क्षेत्रों में साझेदारी के लिए स्वीडन की कंपनियों को आमंत्रित किया। फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री जुहा सिपिला

बेहतर इस्तेमाल करते हुए दोनों प्रधानमंत्रियों ने चेन्नई में ट्रिविट्रोन हेल्थ केयर की अत्याधुनिक मैनुफैक्चरिंग इकाई का टेली-उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पोलैंड के उपप्रधानमंत्री डॉ. पियोट्र ग्लिंस्की के साथ अपनी द्विपक्षीय बातचीत के दौरान अपने गृह राज्य गुजरात के साथ पोलैंड के लम्बे साहचर्य को याद किया। श्री मोदी ने खाद्य परिशोधन, स्वच्छ ऊर्जा एवं परिवहन क्षेत्रों में सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की।

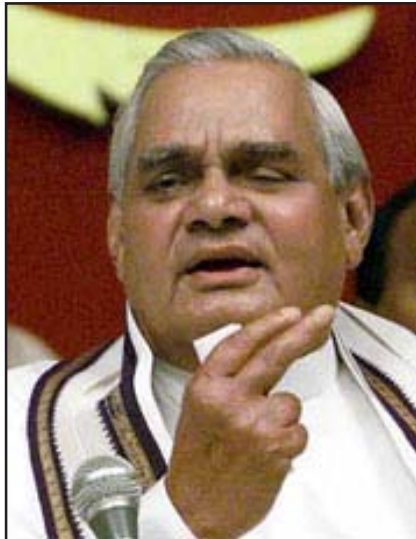
भाजपा के भविष्य से देश का भविष्य जुड़ गया है

– अटल बिहारी वाजपेयी

29-30 नवंबर एवं 1 दिसंबर 1996 को भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश भाजपा अभ्यास वर्क में भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिए गए उद्बोधन के संपादित अंश हम यहां सुधी पाठकों के लिए प्रकाशित कर रहे हैं। प्रस्तुत है उद्बोधन का अंतिम भाग-

अधोसंरचना जरूरी

यह दुर्भाग्य का विषय है कि हमने आर्थिक विकास के साथ विकास के लिए परमावश्यक ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को विकसित करने की ओर ध्यान नहीं दिया है। देश में सड़के नहीं हैं, पुल नहीं हैं, बंदरगाहों और हवाई जहाजों पर समान उतारने और चढ़ाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। बंदरगाहों पर महीनों तक जहाजों को खड़ा रहना पड़ता है। उन्हें डैमरेज देना पड़ता है समुद्र तट से दूर माल उतारने के लिए विवश किया जाता है। प्रमुख हवाई अड्डों का भी यही हाल है। बंदरगाह कम हैं, उनमें स्थान सीमित हैं, उनका विस्तार आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। किन्तु कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देश में बिजली की बढ़ती हुई कमी से गहरा संकट पैदा हो रहा है। बिजली की खपत बढ़ रही है उस मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है। न हमने बिजली की पैदावार की ओर ध्यान दिया और न ही उसकी उचित वितरण की व्यवस्था की है। राज्यों के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भारी घाटे में चल रहे हैं। वितरण में चोरी एक आम बात है। बिजली के बिलों का भुगतान नहीं होता है। अतः जब बिजली संकट सिर पर खड़ा है तो हम हड़बड़ी में विदेशी कंपनियों की अनुचित शर्तें मानकर उनको बिजली पैदा करने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, यह स्थिति गंभीर है। बिजली का



उत्पादन बढ़ाना चाहिये, ऊर्जा विकास की कुंजी है। खेती और उद्योग दोनों के लिए बिजली की जरूरत है। बिजली की मांग निरन्तर बढ़ रही है। हमें एक समृद्धशाली भारत की रचना करनी है। किन्तु समृद्धि के साथ स्वावलम्बन पर भी बल देना जरूरी है। सारा आर्थिक विकास विदेशी पूंजी के बल पर नहीं हो सकता है। यहां आवश्यकता होगी और जिन शर्तों को हम उचित समझेंगे, उन पर विदेशी पूंजी को काम करने की छूट दी जा सकती है आज एक शब्द का प्रयोग होता है वह है- वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी निःसंदेह हमें विश्व के स्तर की चाहिये, पर किस क्षेत्र में? यह विचार हमें टेक्नोलॉजी का स्तर तय करना होगा। सुरक्षा के मामले में विकसित

और प्रयुक्त टेक्नोलॉजी का हम और क्षेत्रों में उपयोग कर सकते हैं। किन्तु एक नई विश्व व्यवस्था के नाम पर विकासशील देशों के सामने जो नया खतरा खड़ा हो रहा है, उस पर विचार करना जरूरी है। कई विकासशील देश छोटे हैं, दुर्बल हैं, उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वे अमीर देशों के दबाव का सामना कर सकें। भौतिक साधनों के साथ उनके पास मानसिक चिन्तन की भी कोई लम्बी परम्परा नहीं है। हमें इस तरह के चिन्तन का सौभाग्य मिला है।

पैसा कमायें पर पैसे के भूखे न बनें

सुख क्या है? मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या मात्र पैसा कमाना? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा कर क्या होगा। सबका जीवन सुखी हो, राष्ट्र में समृद्धि हो, यह तो समझ में आ सकता है लेकिन हर व्यक्ति के मन में पैसे की भूख नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को सुखी होने के लिए कितना पैसा चाहिये। भोग और विलास की भी एक सीमा है। लोकसभा में विश्वास का मत प्राप्त करते हुए मैंने जो भाषण दिया कि आखिर लोग अरबों रुपये जोड़ कर क्या करते हैं। सारा धन, सारी दौलत, सारी पूंजी यहीं पड़ी रह जाएगी, फिर भी अधिकाधिक रुपया जमा करने की होड़ लगी है। गरीब देशों में भोग की एक ऐसी संस्कृति का विकास करने का प्रयास हो रहा है जो विनाश की ओर ले

जा सकती है। हम मन से श्रम करें, अधिक से अधिक कमायें, यह जरूरी है। किन्तु इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है हम अधिक से अधिक बचायें। चीन कुछ मात्र में यह करने में सफल हुआ है। उपभोग को नियंत्रित और बचत को बढ़ाने के लिए केवल आर्थिक चिन्तन ही नहीं, राष्ट्र के प्रति भक्ति को जगाना भी जरूरी है। कम्युनिस्ट देशों ने भी यह किया है। अब कम्युनिस्ट राष्ट्र प्रेम को बुर्जवा संस्कार कहते हैं,

भावना आधार रूप में आ ही जाती है।

आज प्रायः सभी देशों में जड़ों की तलाश का सिलसिला चल रहा है, यहां तक कि जातियां और उपजातियां भी अपनी जड़ों की खोज करना चाहती है। इस्लामी देशों में यह खोज फंडामेंटलिज्म का रूप लेकर सामने आ रही है। मजहब समान होते हुए भी इस्लामी देश संस्कृति की दृष्टि से अलग-अलग हैं, कुछ उदारवादी हैं। कुछ दिन पहले कुछ अमरीकियों से चर्चा करने का मौका

पास एक चिन्तन है, एक विचारधारा है, प्रगति के साधन हैं, इतना बड़ा भूखंड है, पांच-छः हजार साल की संस्कृति है, 90 करोड़ का जन बल है, पुरुषार्थ और पराक्रम की परम्परा है। हमें दृढ़ता से खड़े रहना है। सत्ता का उपयोग हमें इस कार्य के लिए करना है।

भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में उभरी है। हमारी बढ़ती हुई शक्ति और प्रभाव से आतंकित होकर भिन्न-भिन्न विचारों वाले हमारे इर्दगिर्द जमघट बना रहे हैं। पहले कांग्रेस के विरुद्ध गैर कांग्रेसी हवा चलती थी, अब भाजपा के विरुद्ध एकत्रीकरण हो रहा है एकत्रीकरण टिकेगा नहीं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि यदि हमारी प्रगति में रुकावट आयेगी, जो हमारी अपनी की कमियों और खामियों के कारण आयेगी, हमारे विरोधियों के कारण नहीं। यदि हम थोड़ी सी सावधानी और करते, थोड़ा सा परिश्रम और करते तो उत्तर प्रदेश में बहुमत प्राप्त कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ आज देश का भविष्य जुड़ गया है। हमें बहुमत प्राप्त हो या न हो, हमारे विरोधी चाहें या न चाहें, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य और देश का भविष्य एक-दूसरे से सम्बद्ध हो गये हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर हम पिछड़ जायें, हार मान जायें, छोटे-छोटे विवादों में फंस जायें तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी क्षमा नहीं करेगी। देश की स्थिति पर और संगठन की आवश्यकता पर हम कार्यकर्ता के नाते विचार करें, कार्यकर्ता के नाते ही व्यवहार करें। हमारी सफलता-सुनिश्चित है, और आवश्यकता है चिन्तन के अनुरूप सही व्यवहार करने की। ■

(समाप्त)

भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में उभरी है। हमारी बढ़ती हुई शक्ति और प्रभाव से आतंकित होकर भिन्न-भिन्न विचारों वाले हमारे इर्दगिर्द जमघट बना रहे हैं। पहले कांग्रेस के विरुद्ध गैर कांग्रेसी हवा चलती थी, अब भाजपा के विरुद्ध एकत्रीकरण हो रहा है एकत्रीकरण टिकेगा नहीं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि यदि हमारी प्रगति में रुकावट आयेगी, जो हमारी अपनी की कमियों और खामियों के कारण आयेगी, हमारे विरोधियों के कारण नहीं।

किन्तु जब सोवियत संघ पर हिटलर ने हमला किया तो कम्युनिस्ट नेताओं ने प्राचीन इतिहास से पराक्रमी राजाओं और सेनानायकों के जीवन चरित्र निकाल और उन्हें लोगों को प्रेरणा देने के लिए सामने रखा। कम्युनिस्ट परिभाषा के अनुसार सभी पुराने राजा शोषक थे, और निन्दा के अधिकारी थे किन्तु जब उन्हें विदेशी आक्रमण का सामना करना पड़ा तो उनकी भाषा बदल गई। प्राचीन काल के महापुरुषों का उन्हें स्मरण हुआ। बलिदान के लिए इतिहास की वीरतापूर्ण परिभाषा नई पीढ़ी के सामने रखना आवश्यक समझा गया। जब हम समस्याओं को उनकी समग्रता में देखने की बात करते हैं, तो राष्ट्रीयता की

मिला। उनका कहना था कि वे हमारे हिंदुत्व के आन्दोलन को समझते हैं अपनी जड़ों से नाता रखने का प्रयास स्वाभाविक है। किन्तु जड़ों की तलाश भी एक सीमा तक होनी चाहिए। बार-बार जड़ों को उखाड़ कर देखने से पौधे नहीं पनपते। जड़ पेड़ को आधार प्रदान करता है किन्तु पेड़ के लिए जरूरी है, उसका तना हो, उसकी शाखायें हों, शाखाओं में पत्ते हो, पत्तों में फूल खिले और फल लगें। मूल और फल के संबंध को समझना होगा। गरीब देशों की तरह से हमें पश्चिम की चकाचौंध में आने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ इन देशों की आखें भी खुलेगी। हम उसमें उनकी सहायता कर सकते हैं। हमारे

श्रद्धांजलि: पुण्यतिथि-26 फरवरी

विनायक दामोदर सावरकर

शत-शत नमन

विनायक दामोदर सावरकर (जन्म-28 मई, 1883, मृत्यु-26 फरवरी, 1966) न केवल एक क्रांतिकारी थे, बल्कि वे एक भाषाविद्, अप्रतिम क्रांतिकारी, दृढ़ राजनेता, समर्पित समाज सुधारक, दार्शनिक, द्रष्टा, महान् कवि, इतिहासकार और ओजस्वी वक्ता थे। उनके इन्हीं गुणों ने उन्हें महानतम लोगों की श्रेणी में उच्च पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। वीर सावरकर प्रथम क्रान्तिकारी थे, जिन पर स्वतंत्र भारत की सरकार ने झूठा मुकदमा चलाया और बाद में निर्दोष साबित होने पर माफी मांगी। साथ ही वे एक प्रख्यात समाज सुधारक भी थे। उनका दृढ़ विश्वास था, कि सामाजिक एवं सार्वजनिक सुधार बराबरी का महत्त्व रखते हैं व एक-दूसरे के पूरक हैं। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले विनायक दामोदर सावरकर साधारणतया वीर सावरकर के नाम से विख्यात थे।

वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भगूर गांव में हुआ। विनायक दामोदर सावरकर, 20वीं शताब्दी के बड़े हिन्दूवादी थे। उन्हें हिन्दू शब्द से बेहद लगाव था।

वह कहते थे कि उन्हें स्वातन्त्र्य वीर की जगह हिन्दू संगठक कहा जाए। उन्होंने जीवन भर हिन्दू-हिन्दी-हिन्दुस्तान के लिए कार्य किया। वह अखिल भारत हिन्दू महासभा के 6 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए।

1937 में वे 'हिन्दू महासभा' के अध्यक्ष चुने गए और 1938 में हिन्दू



महासभा को राजनीतिक दल घोषित किया था। 1943 के बाद दादर, मुंबई में रहे।

1940 ई. में वीर सावरकर ने पूना में 'अभिनव भारती' नामक एक ऐसे क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर बल-प्रयोग द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। आजादी के वास्ते काम करने के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसायटी बनाई थी, जो 'मित्र मेला' के नाम से जानी गई। एक विशेष न्यायालय द्वारा उनके अभियोग की सुनवाई हुई और उन्हें आजीवन कालेपानी की दुहरी सजा मिली।

सावरकर 1911 से 1921 तक अंडमान जेल (सेल्यूलर जेल) में रहे। 1921 में वे स्वदेश लौटे और फिर 3 साल जेल भोगी। इतनी मुश्किलों के बाद भी वे झुके नहीं और उनका देश-प्रेम का जज्बा बरकरार रहा और अदालत को उन्हें तमाम आरोपों से मुक्त

कर बरी करना पड़ा। मातृभूमि! तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा में ईश्वर सेवा है, यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की।

उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें 'भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध', 'मेरा आजीवन कारावास' और 'अण्डमान की प्रतिध्वनियां' अधिक प्रसिद्ध हैं। जेल में 'हिन्दुत्व' पर शोध ग्रंथ लिखा। 1909 में लिखी पुस्तक 'द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस-1857' में सावरकर ने इस लड़ाई को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई घोषित की थी।

वीर सावरकर ने कलम-कागज के बिना जेल की दीवारों पर पत्थर के टुकड़ों से कविताएं लिखीं। कहा जाता है उन्होंने अपनी रची दस हजार से भी अधिक पंक्तियों को प्राचीन वैदिक साधना के अनुरूप वर्षों स्मृति में सुरक्षित रखा, जब तक वह किसी न किसी तरह देशवासियों तक नहीं पहुंच गई। सावरकर जी की मृत्यु 26 फरवरी, 1966 में मुम्बई में हुई थी। वीर सावरकर के निधन पर भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। सच तो यह है कि महान देशभक्त और क्रांतिकारी सावरकर ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। अपने राष्ट्रवादी विचारों से जहां सावरकर देश को स्वतंत्र कराने के लिए निरन्तर संघर्ष करते रहे वहीं दूसरी ओर देश की स्वतंत्रता के बाद भी उनका जीवन संघर्षों से घिरा रहा। ■

‘देश के किसी भी हिस्से पर देशद्रोही गतिविधियों को सहन नहीं किया जा सकता’

जेएनयू में देशविरोधी नारेबाजी

देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में वामपंथी छात्र संगठनों द्वारा जिस तरह से राष्ट्रविरोधी नारे लगाए गए, वह वास्तव में एक गंभीर चिंता का विषय है। गत 9 फरवरी 2016 को ‘पाकिस्तान जिन्दाबाद’, ‘भारत तेरे टुकड़े होंगे-इंशा अल्लाह-इंशा अल्लाह’, ‘भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी’ नारे लगाए गए, जो कि स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती है। इन देशविरोधी नारों के खिलाफ देशभर में आक्रोश है।

कुछ दिन पहले जवाहरलाल यूनिवर्सिटी (जेएनयू) परिसर में जिस तरह से राष्ट्रविरोधी नारे लगाए गए, भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है और इस प्रकार की गतिविधियों पर चिंता भी व्यक्त करती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि देश की जमीन पर या इसके किसी भी हिस्से पर इस तरह की देशद्रोही गतिविधियों को सहन नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने जेएनयू जाकर जिस तरह से इस घटना का समर्थन किया है, वह सबसे बड़ा चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी देश की रक्षा करने वाले शहीद जवानों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है और हमारा मानना है कि हर राष्ट्रभक्त व्यक्ति एवं संस्थाओं को देश की सीमा की सुरक्षा करनेवाले जवानों के संवेदनाओं की चिंता करना चाहिए।

लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संसद पर हमला करनेवाले आतंकी अफजल गुरु को फांसी की सजा दी गई। उसके बाद आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में देश को तोड़ने के लिए ‘पाकिस्तान जिन्दाबाद’, ‘भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी - जंग रहेगी’, ‘अफजल हम शर्मिन्दा हैं तेरे

कातिल जिन्दा हैं’, ‘हर घर में अफजल होंगे - भारत तेरे टुकड़े होंगे’, जैसे जो नारे लगाए गए, अगर कांग्रेस उपाध्यक्ष, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इसका समर्थन कर रहे हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि इससे बड़ा देशद्रोह का सबूत और क्या हो सकता है। इतना होने के बावजूद, न तो कांग्रेस अध्यक्ष, न कांग्रेस उपाध्यक्ष और न ही कांग्रेस का कोई प्रवक्ता इस घटना के लिए माफी मांगने को तैयार है। आज भी कांग्रेस के प्रवक्ता आतंकी अफजल गुरु को अफजल गुरु ‘जी’ कहकर सम्बोधित कर रहे हैं।

मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह राहुल गांधी द्वारा जेएनयू परिसर में देशद्रोही नारे लगाने वालों के समर्थन में दिए गए बयानों का समर्थन करती है? कांग्रेस पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। मैं श्रीमान राहुल गांधी से यह भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको देशद्रोही गतिविधियों का समर्थन करते वक्त देश की संसद की सुरक्षा करनेवाले शहीद जवानों और उनके परिवारों की संवेदनाओं का ख्याल नहीं आया? आखिर कब तक वोट बैंक की राजनीति की खातिर आप देश के जवानों की शहादत का मजाक उड़ाते रहेंगे? क्या आपको इस बात की चिंता है कि

आप अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में देशद्रोही प्रवृत्तियों को प्रश्रय देने से भी नहीं चूक रहे? इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।

देश की जनता यह जानना चाहती है कि आखिर अभिव्यक्ति की आजादी की कांग्रेस की व्याख्या क्या है। देश की जनता यह जानना चाहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर छात्रों को अपनी बात कहने देने का मतलब हिन्दुस्तान को टुकड़े करना है क्या? देश की जनता यह जानना चाहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब आतंकी अफजल गुरु का समर्थन करना है क्या? देश की जनता यह जानना चाहती है कि कांग्रेस देश के सर्वोच्च अदालत के फैसले को मानती है या नहीं?

भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि कांग्रेस पार्टी को इन सब बातों का स्पष्टीकरण देना चाहिए। यदि कांग्रेस के दिल में शहीदों के परिवारों के प्रति थोड़ी सी भी संवेदना है और उसे यदि लगता है कि देशद्रोहियों का समर्थन नहीं करना चाहिए तो कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को देशवासियों से अविलंब माफी मांगनी चाहिए। ■

क्या यही है कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति की नई परिभाषा?

✎ अमित शाह

केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की सफलता से निराश और हताश कांग्रेस गहरे अवसाद से ग्रस्त है। पार्टी और उसके नेता यह समझ नहीं पा रहे हैं कि इस अवसाद की अवस्था में वो देश के समक्ष कैसे एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभायें।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तो इस हताशा में देश विरोधी और देश हित का अंतर तक नहीं समझ पा रहे हैं। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में जो कुछ भी हुआ उसे कहीं से भी देश हित के दायरे में रखकर नहीं देखा जा सकता है। देश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगे और आतंकवादियों की खुली हिमायत हो, इसे कोई भी नागरिक स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं ने जेएनयू जाकर जो बयान दिए हैं उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी सोच में राष्ट्रहित जैसी भावना का कोई स्थान नहीं है।

जेएनयू में वामपंथी विचारधारा से प्रेरित कुछ मुट्ठीभर छात्रों ने निम्नलिखित राष्ट्रविरोधी नारे लगाए:

- ▶ “पाकिस्तान जिंदाबाद”
- ▶ “गो इंडिया गो बैक”
- ▶ “भारत की बरबादी तक जंग रहेगी जारी”
- ▶ “कश्मीर की आजादी तक जंग

रहेगी जारी”

- ▶ “अफजल हम शर्मिन्दा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं”
- ▶ “तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा”
- ▶ “अफजल तेरे खून से इन्कलाब आयेगा”

इन छात्रों को सही ठहराकर राहुल गांधी किस लोकतांत्रिक व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी के लिए राष्ट्रभक्ति की परिभाषा यही है? देशद्रोह को छात्र क्रान्ति और देशद्रोह के खिलाफ कार्यवाही को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात का नाम देकर उन्होंने राष्ट्र की अखण्डता के प्रति संवेदनहीनता का परिचय दिया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इन नारों का समर्थन करके क्या उन्होंने देश की अलगाववादी शक्तियों से हाथ मिला लिया है? क्या वह स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आड़ में देश में अलगाववादियों को छूट देकर देश का एक और बंटवारा करवाना चाहते हैं?

देश की राजधानी में स्थित एक अग्रणी विश्वविद्यालय के परिसर को आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का केंद्र बना कर इस शिक्षा के केंद्र को बदनाम करने की साजिश की गयी। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि क्या केंद्र सरकार का हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना राष्ट्रहित में होता? क्या आप

ऐसे राष्ट्र विरोधियों के समर्थन में धरना देकर देशद्रोही शक्तियों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं?

जेएनयू में राहुल गांधी ने वर्तमान भारत की तुलना हिटलर की जर्मनी से कर डाली। इतनी ओछी बात करने से पहले वह भूल जाते हैं कि स्वतंत्र भारत की हिटलर की जर्मनी से सबसे निकट परिकल्पना सिर्फ श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए 1975 के आपातकाल से की जा सकती है। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति तो दूर, आपातकाल में विरोधियों को निर्ममता के साथ जेल में टूंस दिया गया था। वामदलों के नेता जिनकी वह आज हिमायत करते घूम रहे हैं, वह भी इस बर्बरता के शिकार हुए थे। हिटलरवाद सिर्फ कांग्रेस के डी. एन.ए. में है, भाजपा को राष्ट्रवाद और प्रजातंत्र के मूल्यों की शिक्षा कांग्रेस पार्टी से लेने की जरूरत नहीं है। हमारे राजनैतिक मूल्य भारतवर्ष की समृद्ध संस्कृति से प्रेरित हैं और भारत का संविधान हमारे लिए शासन की निर्देशिका है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूँ कि 1975 का आपातकाल क्या उनकी पार्टी के प्रजातांत्रिक मूल्यों को परिभाषित करता है और क्या वह श्रीमती इंदिरा गांधी की मानसिकता को हिटलरी मानसिकता नहीं मानते?

देश की सीमाओं की रक्षा और

शेष पृष्ठ 18 पर

वामपंथी अतिवाद से देशविरोधी ताकतें मजबूत

डा. शिव शक्ति बक्सी

सन् 2004 की बात है, चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को अपने मानचित्र में दिखाए जाने पर पूरे देश में आक्रोश था। जेएनयू छात्रसंघ की बैठक में इसके विरुद्ध एक प्रस्ताव लाया गया जो भारी बहुमत से गिर गया। एसएफआई, एआईएसएफ और आइसा के जो नेता आज गला फाड़-फाड़कर स्वयं को भारत की एकता एवं अखंडता का समर्थक बता रहे हैं, वे चीन के विरुद्ध इस प्रस्ताव के विरुद्ध थे। इसी प्रकार 2015 में जब यह प्रस्ताव आया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, आइसा, एसएफआई और एआईएसएफ के काउंसिलरों ने इसके विरुद्ध मतदान कर इसे गिरा दिया। इस बैठक की अध्यक्षता कन्हैया कुमार कर रहे थे। अब इनका यह दावा की वे हमेशा देश की एकता एवं अखंडता के पक्षधर रहे हैं, जेएनयू की छात्र राजनीति को समझने वालों के लिये एक नया रहस्योद्घाटन प्रतीत हो रहा है। इस तरह की घटनाएं कोई एक बार नहीं घटी, बल्कि बार-बार इसे दुहराया गया है। कश्मीरी पंडितों का प्रश्न हो या राष्ट्रगीत वंदे मातरम् का विषय, सभी प्रस्ताव खारिज होते रहे हैं। यदि जेएनयू छात्रसंघ के पारित प्रस्तावों को गहराई से अध्ययन किया जाय तो वामपंथी छात्र राजनीति का पूरा चरित्र ही बेनकाब हो जायेगा।

यूं तो जेएनयू में वामपंथी छात्र संगठन आपस में बंटे हुए हैं लेकिन जहां तक विद्यार्थी परिषद् से विरोध का प्रश्न है, वे एकजुट हैं। वे इस प्रकार से अपनी चुनावी रणनीतियां बनाते हैं ताकि उनका

छात्रसंघ पर सामूहिक कब्जा बना रहे। एक ओर जहां अतिवादी तत्व वामपंथी एजेंडे पर कब्जा करने को प्रयासरत रहते हैं, सीपीआई एवं सीपीएम के छात्र संगठन बराबर इनसे 'असली वामपंथी' होने का प्रमाण पत्र पाने की जुगत में रहते हैं। विद्यार्थी परिषद् का विरोध करने के साथ-साथ उन पर वामपंथ के अंदर की बहस में भी स्वयं को 'असली वामपंथी' साबित करने का दबाव रहता है। 'असली वामपंथी' साबित करने की इस प्रतियोगिता में यदि एक गुट जम्मू-कश्मीर में 'आफप्सा' हटाने की बात करते हैं तो दूसरा एक कदम आगे बढ़कर 'जम्मू-कश्मीर' को देश से अलग होने के 'आत्म निर्णय के अधिकार' की वकालत करता है। कहीं पीछे न छूट जाये यह सोचकर अन्य गुट 'कश्मीर की आजादी' के लिए कार्यक्रम तक आयोजित कर देता है। अब सारे गुट मिलकर एक जगह जुटकर नारेबाजी और डफली बजाने में एक-दूसरे से

कश्मीरी पंडितों का प्रश्न हो या राष्ट्रगीत वंदे मातरम् का विषय, सभी प्रस्ताव खारिज होते रहे हैं। यदि जेएनयू छात्रसंघ के पारित प्रस्तावों को गहराई से अध्ययन किया जाय तो वामपंथी छात्र राजनीति का पूरा चरित्र ही बेनकाब हो जायेगा।

बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते दिखते हैं। इस तरह की परस्पर स्पर्धा के बीच जेएनयू का वामपंथी अतिवादी संक्रमण का शिकार हो चुका है। सभी वामपंथी गुट एक-दूसरे को पीछे धकेल स्वयं को 'असली वामपंथी' बताने की गलाकाट स्पर्धा में डूबे हुए हैं। उनकी 'वोट बैंक' की राजनीति अब उन्हें बाध्य करती है कि 'अतिवादी वामपंथी' तथा 'जिहादी तत्वों' के घालमेल को एक वैचारिक जामा पहना कर राजनैतिक फसल काटी जाये। इसका परिणाम दंतेवाड़ा में सैनिकों के शहीद होने पर जश्न और अफजल गुरु एवं मकबूल भट्ट को 'शहीद' बताने के रूप में सामने आता है।

जिन्हें इस पूरे प्रकरण में छात्र संघ अध्यक्ष की संलिप्तता में संदेह है उन्हें पता रहना चाहिए कि कैंपस के अंदर वहां के छात्र-शिक्षक के चाहे बिना कोई बाहरी तत्व विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता। एक ओर जहां तथाकथित 'सांस्कृतिक संध्या' जिसमें भारत विरोधी एवं पाकिस्तान परस्त नारे लगाये गये कन्हैया कुमार के नेतृत्व वाली छात्र संघ के धड़े के दबाव में आयोजित हुआ, वहीं दूसरी ओर इन नारों तथा नकाबपोश लोगों की उपस्थिति का कन्हैया कुमार ने ना कोई विरोध किया ना ही उनके विरुद्ध कोई शिकायत जेएनयू प्रशासन या पुलिस को दी। वे उनका समर्थन करते और उत्साह बढ़ाते दिखाई दे रहे थे। कुछ वीडियो में तो वे इस पूरी घटना के मुख्य आयोजक उमर खालिद के साथ नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में जेएनयू की इस घटना को

अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता। ऐसा नहीं है कुछ मुट्ठीभर लोग इकट्ठे हुए और अति उत्साह के कुछ नारे लगा बैठे। यह सब भारत को कमजोर करने के लिए युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट करने के एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। भारत विरोधी तत्व विभिन्न परिसरों में इस तरह की स्थितियां पैदा कर रहे हैं, इसलिये यह आवश्यक है कि इसकी पूरी जांच करके इस तरह की साजिश को बेनकाब किया जाय। यह वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रसंघ के पदाधिकारियों की उपस्थिति में और उनके समर्थन से भारत विरोधी नारे लगे और कन्हैया कुमार ने इसका कोई विरोध नहीं किया। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाय कम है।

पूरे देश में इस घटना से लोग न केवल आहत हैं बल्कि आक्रोश में हैं। सभी राजनैतिक दल तथा जेएनयू समुदाय को इस राष्ट्रीय आक्रोश पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पुलिस कार्रवाई पर प्रश्न खड़े करके इस पूरे मुद्दे को दरकिनार करने के प्रयास से जेएनयू की छवि लोगों के बीच और भी अधिक धूमिल होगी। अब समय आ गया है कि वामपंथी दलों को आत्ममंथन कर अपनी राजनीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि जेएनयू में इस तरह के वातावरण की जिम्मेदारी से वे बच नहीं सकते। अतिवाद की स्पर्धा से देश विरोधी तत्वों के हाथ मजबूत हुए हैं जो विश्वविद्यालयों में अपने लिए नये रंगरूट तलाश रहे हैं। जिस प्रकार से जेएनयू का एक वर्ग इस पूरे मुद्दे पर लोगों की आंखों में धूल झाँकने का प्रयास कर रहा है, देश में इसका बहुत बुरा संदेश गया है और लोगों का गुस्सा बढ़ा है। राहुल गांधी ने देश के इस गुस्से को समझे बिना जिस प्रकार से इस घटना का समर्थन किया उससे कांग्रेस के लिए दुविधापूर्ण स्थिति खड़ी हो गई है। कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता कि राष्ट्रीय मुद्दों पर सभी राजनैतिक दलों को एकजुट होकर खड़े होना चाहिए। जितना जल्दी यह बात सब समझ जायें देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। ■

पृष्ठ 16 का शेष...

कश्मीर में अलगाववाद को नियंत्रित करते हुए हमारे असंख्य सैनिक वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। 2001 में देश की संसद में हुए आतंकवादी हमले में दिल्ली पुलिस के 6 जवान, 2 संसद सुरक्षाकर्मी और एक माली शहीद हुए थे। इसी आतंकी हमले के दोषी अफजल गुरू का महिमामंडन करने वालों और कश्मीर में अलगाववाद के नारे लगाने वालों को समर्थन देकर राहुल गांधी अपनी किस राष्ट्रभक्ति का परिचय दे रहे हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी हाल में सियाचिन में देश की सीमा के प्रहरी 10 सैनिकों जिनमे लांस नायक हनुमंथप्पा एक थे के बलिदान को क्या वह इस तरह की श्रद्धांजली देंगे?

भाजपा के केंद्र की सत्ता में आने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से कश्मीर में भी देश विरोधी भावनाओं को नियंत्रित करने में सफलता मिल रही है। लेकिन प्रमुख विपक्षी दल होने के बावजूद कांग्रेस इस काम में सरकार को सहयोग करने के बजाए जेएनयू में घटित शर्मनाक घटना को हवा दे रही है। प्रगतिशीलता के नाम पर वामपंथी विचारधारा का राष्ट्रविरोधी नारों को समर्थन किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मैं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी और उपाध्यक्ष राहुल गाँधी से ऊपर उल्लिखित सवालों का 125 करोड़ देशवासियों की ओर से जवाब मांगता हूँ और यह भी मांग करता हूँ कि राहुल गाँधी अपने इस कृत्य के लिए देश से माफी मांगें। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।)

जाट आरक्षण को लेकर भाजपा समिति का गठन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने जाट आरक्षण के सम्बन्ध में वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्री श्री वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है जिसके सदस्य निम्न रहेंगे:-

- श्री सतपाल मलिक (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व केन्द्रीय मंत्री)
- श्री अविनाश राय खन्ना (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सांसद राज्य सभा)
- श्री डा. महेश शर्मा (केन्द्रीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार)
- श्री संजीव बालियान (केन्द्रीय राज्य मंत्री)

यह कमेटी जाट आरक्षण से सम्बन्धित सभी पहलुओं का अध्ययन कर एवं सभी पक्षों को सुनकर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्र सरकार को शीघ्रातिशीघ्र सौंपेगी। ■

मनमोहन सिंह को अपनी पार्टी को क्या नसीहत देनी चाहिए?

✎ अरुण जेटली

भू तपूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कभी-कभार ही सार्वजनिक तौर पर बयान देते हैं, लेकिन जब वो कोई बात कहते हैं, तो देश को पूरी तन्मयता से उन्हें सुनना चाहिए। ये राष्ट्र के विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनसे दलगत राजनीति से परे होने की उम्मीद की जाती है, रचनात्मक सलाह की अपेक्षा की जाती है और यहाँ तक कि उनसे समय-समय पर व्यापक राष्ट्रीय हित में कार्य करने के उद्देश्य से अपने राजनीतिक दल को भी एक सशक्त संदेश देने की उम्मीद की जाती है। पूरे सम्मान के साथ मैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से ऐसी ही अपेक्षा रखता हूँ।

मैंने 'इंडिया टुडे' के नवीनतम संस्करण में उनका साक्षात्कार पढ़ा, विशेष रूप से उनकी इस चिंता के बारे में कि प्रधानमंत्री और सरकार विपक्ष से संवाद स्थापित नहीं करती। उनका मानना है कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं कर रही है।

मुझे यकीन है कि अगर डॉ. सिंह ने निष्पक्षतापूर्वक वर्तमान सरकार का विश्लेषण किया होता, तो वास्तव में उनको एहसास हुआ होता कि भारत में एक ऐसी सरकार है जहाँ प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम समझा जाता है, जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का बिना भ्रष्टाचार के पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन होता है, जहाँ उद्योगपतियों को अपनी

विपक्ष के साथ विचार-विमर्श के दौरान कांग्रेस को छोड़कर लगभग सभी विपक्षी राजनीतिक दलों ने जीएसटी का समर्थन किया था लेकिन कांग्रेस ने यू-टर्न ले लिया। संसदीय मामलों के मंत्री और खुद मैंने संसद में हर वरिष्ठ कांग्रेस नेता के साथ जीएसटी पर विचार-विमर्श किया है। क्या कांग्रेस की 'संवैधानिक कैप' पर स्थिति राजनीति से प्रेरित नहीं है? एक अर्थशास्त्री के तौर पर डॉ. सिंह को अपनी पार्टी को सलाह देनी चाहिए कि संविधान में कर की दरें निर्धारित करने की व्यवस्था नहीं की गई है। राष्ट्र वरिष्ठ नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्रियों जैसे राजनीतिज्ञों से यही अपेक्षा रखती है।

फाइलों के निपटारे अथवा किसी निर्णय के लिए नॉर्थ ब्लॉक का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता, जहाँ पर्यावरण संबंधी मंजूरी नियमित तौर पर निष्पादित की जाती हैं, न कि इन्हें किसी दुर्विचारों अथवा पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर रोका जाता है। क्या वाकई सरकार की कार्य संस्कृति में कोई बदलाव नहीं आया है? यूपीए सरकार के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को न तो नॉर्थ ब्लॉक द्वारा और न ही स्वयं के बोर्डों द्वारा चलाया जा रहा था बल्कि वे 24, अकबर रोड से नियंत्रित होते थे।

ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बुनियादी चुनौतियों को संप्रग सरकार के दौरान सुलझाया नहीं गया। यह वर्तमान सरकार है जो विगत की इन चुनौतियों का समाधान कर रही है।

कई ठप्प पड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं अब शुरू हो चुकी हैं। बड़ी चुनौतियों के बावजूद, विश्व पटल पर, भारत की छवि 'पालिसी-पैरालाइसिस' से निकलकर 'बेहतर संभावनाओं' वाले देश के रूप में परिवर्तित होने की यात्रा, सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ने की है।

विपक्ष के साथ विचार-विमर्श के दौरान कांग्रेस को छोड़कर लगभग सभी विपक्षी राजनीतिक दलों ने जीएसटी का समर्थन किया था लेकिन कांग्रेस ने यू-टर्न ले लिया। संसदीय मामलों के मंत्री और खुद मैंने संसद में हर वरिष्ठ कांग्रेस नेता के साथ जीएसटी पर विचार-विमर्श किया है। क्या कांग्रेस की 'संवैधानिक कैप' पर स्थिति राजनीति से प्रेरित नहीं है?

एक अर्थशास्त्री के तौर पर डॉ. सिंह को अपनी पार्टी को सलाह देनी चाहिए कि संविधान में कर की दरें निर्धारित करने की व्यवस्था नहीं की गई है। राष्ट्र वरिष्ठ नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्रियों जैसे राजनीतिज्ञों से यही अपेक्षा रखती है। ■

(लेखक केंद्रीय वित्त एवं सूचना व प्रसारण मंत्री हैं।)

खाद्य सुरक्षा, सभी के लिए आवास और सब्सिडी पर जोर

गत 23 फरवरी 2016 को संसद के दोनों सदनो के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने संबोधित किया। हम यहां उनके द्वारा दिए गए अभिभाषण का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं :-

- ▶ दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानवता दर्शन के बारे में कहा था, जिसमें अंत्योदय की परिकल्पना की गई है तथा इसमें आखिरी व्यक्ति तक अवसरों की सशक्त किरणें पहुंचती हैं। यह सिद्धांत मेरी सरकार का सभी कार्यक्रमों में मार्गदर्शन करता है। मेरी सरकार ने विशेष रूप से 'गरीबों की उन्नति' (गरीबी उन्मूलन), 'किसानों की समृद्धि' (किसान समृद्धि) और 'युवाओं को रोजगार' पर ध्यान केंद्रित किया है।
- ▶ मेरी सरकार ने वित्तीय समग्रता और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से इस लक्ष्य को संभव बनाने का वादा किया है। ये दोनों ऐसे पंख हैं, जिन पर मानवीय आकांक्षा उड़ान भरती है। इसके लिए मेरी सरकार ने खाद्य सुरक्षा, सभी के लिए आवास और सब्सिडी पर जोर दिया है, ताकि इनका लाभ उन लोगों तक पहुंच सकें, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पिछले साल, मैंने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन-धन योजना के बारे में बात की थी। आज, मुझे यह कहने में गर्व हो रहा है कि यह विश्व का सबसे सफल वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत, इक्कीस करोड़ से भी अधिक खाते खोले गए हैं, जिसमें से पंद्रह करोड़ रुपए से अधिक खातें क्रियात्मक हैं और इन खातों में कुल मिलाकर बत्तीस हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। यह कार्यक्रम न केवल बैंक खाते खोलने तक सीमित है, बल्कि गरीबों बुनियादी वित्तीय सेवायें और सुरक्षा प्रदान करके गरीबी उन्मूलन के लिए एक मंच भी बन गया है।
- ▶ सामाजिक सुरक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए मेरी सरकार ने तीन नई बीमा और पेंशन योजनाओं - प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति

बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की शुरुआत की है, जो समाज के वंचित वर्गों को बीमा कवर उपलब्ध कराती हैं।

- ▶ सरकार 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून, 2015 को शुरू की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों, शहरी गरीबों, आर्थिक



रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों के लोगों के लाभ के लिए लगभग 2 करोड़ मकान बनाने का प्रावधान है। इस मिशन में आगामी पांच वर्षों के दौरान 4041 वैधानिक कस्बों को शामिल किया जाएगा। पहले वर्ष के दौरान 27 राज्यों में 2011 कस्बों/शहरों इस मिशन के अधीन शामिल किया गया है। 24,600 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से चार लाख पच्चीस हजार घरों के निर्माण की मंजूरी दी गई है।

- ▶ लक्षित सब्सिडी सुनिश्चित करती है कि इसका लाभ वांछनीय व्यक्ति तक पहुंचे। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को अब तक मेरी सरकार द्वारा वित्त पोषित 42 योजनाओं तक बढ़ा दिया गया है। पहल योजना विश्व में अपनी किस्म की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण कार्यक्रम बन गई है। इससे लगभग 15 करोड़ लोग लाभान्वित

- हो रहे हैं। जून 2014 के बाद से खाद्य सुरक्षा कवरेज दुगुनी होकर 68 करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों तक पहुंच गई है।
- ▶ गिव-बैक कार्यक्रम के साथ अपनी मर्जी से सब्सिडी छोड़ने के अभियान से प्राप्त सब्सिडी के कारण 50 लाख बीपीएल परिवारों को नये एलपीजी कनेक्शन जारी किये गये हैं। 62 लाख से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं ने स्वेच्छा से इस अभियान के तहत अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी है। 2015 के दौरान ग्रामीण गरीबों के लिए सबसे अधिक नए रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए गए।
 - ▶ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को उचित संशोधनों के द्वारा और मजबूत बनाया गया है। सामाजिक समग्रता की भावना को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 वीं जयंती मनाई जा रही है। 26 नवंबर को संविधान को अपनाया गया था और अब इसे देश के नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरी सरकार डॉ. अंबेडकर की विरासत के पांच स्थलों के संरक्षण के लिए काम कर रही है
 - ▶ मेरी सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के 50 प्रतिशत से अधिक बजट को छात्रवृत्ति धन के लिए आवंटित कर दिया है। पारसी समुदाय के जीवन इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए अगले महीने एक प्रदर्शनी अनंत लौ (एवरलास्टिंग लेम) का आयोजन किया जा रहा है।
 - ▶ मेरी सरकार ने अभी हाल ही में किसानों के अनुकूल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है, जो किसानों के लिए सबसे कम प्रीमियर दर पर फसल बीमा देने के लिए सरकार का सबसे बड़ा अंशदान है। इस योजना में पहली बार बाढ़ और बेमौसम बारिश के कारण फसल कटाई की हानियों की राष्ट्रीय कवरेज, सरकारी सब्सिडी जल्दी उपलब्ध कराना और कोई दावों के शीघ्र तथा सही निपटान के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग जैसी बातों को शामिल किया गया है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को सहायता की राशि बढ़ाकर 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है और इसके लिए पात्रता मानदंडों में छूट दी गई है।
 - ▶ मार्च, 2017 तक सभी 14 करोड़ कृषि जोत के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये जाएंगे और जिसके कारण उर्वरकों के न्यायसंगत प्रयोग इनपुट लागत कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकेगा।
 - ▶ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जल उपयोग दक्षता सुधार कर और सूखारोधी बनाकर खेती का विस्तार करने के लिए सुनिश्चित सिंचाई का वादा किया गया है। मेरी सरकार 'पर ड्रॉप मोर क्रोप' तथा 'जल संचय फोर जल सिंचन' के दर्शन के लिए प्रतिबद्ध है।
 - ▶ मेरी सरकार ने कृषि उच्च शिक्षा को मजबूत करने, 109 नए कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने और तीन नई कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करने के लिए कदम उठाए हैं। किसानों के लाभ के लिए नीति पहल, मूल्यों और अन्य कृषि से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 247 किसान चैनल शुरू किया गया है।
 - ▶ पिछले 19 महीनों के दौरान पांच नए मेगा फूड पार्कों में काम शुरू हो गया है। पिछले 18 महीनों में कोल्ड चैन योजना के तहत 33 परियोजनाएं चालू की गई है।
 - ▶ 14वें वित्त आयोग ने 2015-16 से पांच साल की अवधि के लिए केवल ग्राम पंचायतों के लिए दी गई दो लाख करोड़ रुपये की अंशदान राशि को राज्यों ने बड़े उत्साह से प्राप्त किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन भी कौशल और स्थानीय उद्यमिता के विकास और बुनियादी ढांचे सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 300 ग्रामीण विकास समूहों के लिए शुरू किया गया है।
 - ▶ युवा हमारे देश के भविष्य हैं और व्यापक रोजगार सृजन के जरिये 'युवाओं को रोजगार' सुनिश्चित करना मेरी सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य है। हम मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा, कुशल भारत जैसी पहलों के जरिये रोजगार सृजन में तेजी ला रहे हैं।
 - ▶ मेरी सरकार की अभिनव पहलों से भारत को विश्व बैंक की 'कारोबार में सुगमता' वाली नवीनतम रैंकिंग में 12 पायदान ऊपर चढ़ने में मदद मिली है। एक खास बात यह भी है कि प्रतिकूल वैश्विक निवेश माहौल के बावजूद 'मेक इन इंडिया' पहल ने एफडीआई के प्रवाह में 39 फीसदी बढ़ोतरी हासिल की है।
 - ▶ मेरी सरकार ने 'कारोबार में सुगमता' बढ़ाने के लिए

- विभिन्न राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी सहयोग को बढ़ावा दिया है। प्रक्रिया के सरलीकरण, ई-आधारित प्रक्रिया शुरू करने और बेहतर निवेश माहौल के लिए बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में निवेश हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उनकी सहायता भी की जा रही है।
- ▶ सूक्ष्म, लघु, मझोले उद्यम (एमएसएमई) बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया कराते हैं। बैंकों ने प्रधानमंत्री की 'मुद्रा योजना' के तहत 2.6 करोड़ से भी अधिक कर्जदारों को 1 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा की राशि मुहैया कराई है, जिनमें से 2.07 करोड़ महिला उद्यमी हैं।
 - ▶ मेरी सरकार के 'कुशल भारत' संबंधी मिशन ने गति पकड़ ली है और पिछले वर्ष तकरीबन 76 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया।
 - ▶ उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के नये संस्थान स्थापित किये गये हैं। छह भारतीय प्रबंधन संस्थानों, एक भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान और एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने काम करना शुरू कर दिया है।
 - ▶ स्वस्थ भारत का सर्वोत्तम तरीका खेलकूद है। मेरी सरकार ने गुवाहाटी और शिलांग में 5 फरवरी से लेकर 16 फरवरी, 2016 तक 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया।
 - ▶ मेरी सरकार अपने स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिये अंतर-संस्थान रैंकिंग प्रणाली 'कायाकल्प' से उचित लाभ उठा रही है।
 - ▶ मेरी सरकार समग्र स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा की आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और होम्योपैथी प्रणालियों को मजबूत बनाने पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है। प्रथम 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' विश्व भर में बड़े उत्साह के साथ 21 जून, 2015 को मनाया गया।
 - ▶ मेरी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर सुगम्य भारत अभियान शुरू किया है, ताकि सामुदायिक जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
 - ▶ स्वच्छ भारत मिशन एक सामुदायिक आंदोलन का स्वरूप लेता जा रहा है, ताकि लोगों खासकर गरीबों के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य में व्यापक बदलाव आ सके।
 - ▶ मेरी सरकार ने 'जल क्रांति अभियान' शुरू किया है, जिससे कि इस आम-जन केन्द्रित कार्यक्रम के जरिये जल संरक्षण एवं प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ सके।
- नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मेरी सरकार सभी 118 शहरों में अनेक परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही है।
- ▶ जहां एक ओर मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म करने के लिए कदम उठाये हैं, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार के दोषी लोगों को दण्डित करने में मेरी सरकार कठोर रुख अख्तियार कर रही है।
 - ▶ बुनियादी ढांचागत विकास को नई गति प्रदान करने से सभी लोगों के लिए अवसर प्राप्त हुए हैं। मेरी सरकार ने शहरों के विकास को चुनौती मानते हुए 'स्मार्ट सिटी' कार्यक्रम शुरू किया है।
 - ▶ स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को वर्ष 2020 तक कई गुना बढ़ाकर 175 गीगावाट के स्तर पर पहुंचाने की परिकल्पना की है।
 - ▶ सरकार के सत्ता संभालने के बाद से लेकर अब तक ऊर्जा की किल्लत 4 फीसदी से घटकर 2.3 फीसदी के स्तर पर आ गई है।
 - ▶ मेरी सरकार ने कोयला क्षेत्र में व्यापक सुधार लागू किये हैं और 70 से भी ज्यादा कोल ब्लॉकों की पारदर्शी नीलामी/आवंटन किया है।
 - ▶ खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने और खनिज संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए खान एवं खनिज विकास और नियमन अधिनियम, 1957 को संशोधित किया गया है और खदानों की नीलामी शुरू कर दी गई है।
 - ▶ मेरी सरकार ने हाल ही में असम गैस क्रैकर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। इस परियोजना से तकरीबन 1 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार सृजित होने की आशा है।
 - ▶ मेरी सरकार ने रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में साफ-सफाई के मानकों को बेहतर करने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी उपाय किये हैं।
 - ▶ जापान की सरकार के साथ हुए ऐतिहासिक समझौते के परिणामस्वरूप मुम्बई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर एक वास्तविकता में तब्दील हो जायेगी।
 - ▶ मार्च, 2019 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1 लाख 78 हजार ग्रामीण बस्तियों को ऐसी सड़कों से जोड़ दिया जायेगा जो हर मौसम में कारगर साबित होंगी।■

कैबिनेट ने व्यापार सुविधा समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के व्यापार सुविधा समझौते (टीएफए) के तहत प्रतिबद्धताओं की अधिसूचना के लिए प्रस्ताव, विश्व व्यापार संगठन के सचिवालय में टीएफए के प्रोटोकॉल की स्वीकृति के प्रपत्र की संपुष्टि एवं स्वीकृति और राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति (एनसीटीएफ) के गठन को मंजूरी दे दी है।

व्यापार सुविधा समझौते में वस्तुओं की आवाजाही, उन्हें जारी करने और स्वीकृति देने में तेजी लाने के लिए प्रावधान हैं, जिनमें पारगमन वाली वस्तुएं भी शामिल हैं। इस समझौते में व्यापार सुविधा और कस्टम के अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर कस्टम एवं अन्य उपयुक्त प्राधिकरणों में कारगर सहयोग के लिए विभिन्न उपायों का भी उल्लेख किया गया है। ये उद्देश्य भारत की 'कारोबार में सुगमता' वाली पहल के अनुरूप ही हैं।

डब्ल्यूटीओ के दो-तिहाई सदस्यों की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद ही अधिसूचित सदस्यों के लिए व्यापार सुविधा समझौता प्रभावी माना जाएगा। समझौते के प्रावधानों के क्रियान्वयन और घरेलू तालमेल दोनों में ही सहूलियत के लिए राजस्व विभाग के सचिव और वाणिज्य विभाग के सचिव की संयुक्त अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति गठित की जाएगी।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अभिनव के क्षेत्र में सहयोग पर ब्रिक्स समझौते ज्ञापनपत्र पर हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अभिनव के क्षेत्र में सहयोग पर ब्रिक्स समझौते ज्ञापनपत्र पर हस्ताक्षर की जानकारी दी। भारत ने तीसरी ब्रिक्स एसटीआई मंत्रिस्तरीय बैठक के अवसर पर ब्राजील के ब्रासीलिया में मार्च, 2015 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अभिनव के क्षेत्र में सहयोग पर ब्रिक्स समझौते ज्ञापनपत्र पर हस्ताक्षर किए थे।

इस समझौते में आपसी सहमति से विज्ञान और प्रौद्योगिकी गतिविधियों के माध्यम से ब्रिक्स देशों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अभिनव के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहन देना शामिल है। इस समझौते ज्ञापन पत्र का उद्देश्य ब्रिक्स देशों

के बीच एसटीआई में साझा अनुभवों का उपयोग करते हुए समान वैश्विक और क्षेत्रीय समाजिक-आर्थिक चुनौतियों के समाधान के लिए एसटीआई में सहयोग के रणनीतिक प्रारूप को स्थापित करना है।

भारत की ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य ब्रिक्स देशों के समान मंत्रालय, नोडल मंत्रालयों/विभागों के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर ब्रिक्स समझौते ज्ञापन पत्र के उद्देश्यों को यथार्थ रूप देने के लिए निर्धारित क्षेत्रों में सहयोग, प्रारूपों और तंत्रों को आपसी सहमति से तय करेंगे और ब्रिक्स देशों के बीच संबंधित राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप संयुक्त निधियन का निर्धारण किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने लिगो-भारत वृहत् विज्ञान प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी को गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान के लिए लिगो-भारत वृहत् विज्ञान प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। परमाणु ऊर्जा तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा लिगो-भारत परियोजना (लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रैविटेशनल-वेव ओब्ज़रवेटरी इन इंडिया) के नाम से प्रसिद्ध प्रस्ताव को शुरू किया गया है। यह मंजूरी उस समय दी गई है, जब कुछ दिन पहले ही गुरुत्वाकर्षण तरंगों की ऐतिहासिक खोज की गई है, जिससे ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने की नई खिड़की खुली है।

देश में गुरुत्वाकर्षण तरंगों की वेधशाला, लिगो-भारत परियोजना अमरीका में लिगो प्रयोगशाला चलाने वाली केल्टेक और एमआईटी के सहयोग से स्थापित की जाएगी। इस परियोजना से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को गुरुत्वाकर्षण तरंगों की गहराई में जाकर अध्ययन करने और नये खगोलीय क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा।

लिगो-भारत से भारतीय उद्योग के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे समतल भू-भाग में अल्ट्रा हाई वैक्यूम पर 8 किलोमीटर लम्बे बीम ट्यूब का निर्माण किया जाएगा।

इस परियोजना से भारतीय छात्रों और युवा वैज्ञानिकों को ज्ञान के नये क्षेत्रों को तलाशने की प्रेरणा मिलेगी और देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र को और प्रोत्साहन मिलेगा। ■

शहरी गरीबों के लिए 4,076 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 81,757 मकानों को मंजूरी

केंद्र 1,226 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करायेगा

केन्द्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 4,976 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 7 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 86,179 मकानों का निर्माण करने को 18 फरवरी को मंजूरी प्रदान की। इसके लिए, मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत शहरों में रहने वाले गरीबों को लाभांशित करने के लिए 1.50 लाख रुपये प्रति मकान की दर से कुल 1,226 करोड़ रुपये की कुल केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा।

डॉ. नंदिता चटर्जी, सचिव (एचयूपीए) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय अनुमोदन एवं निगरानी समिति ने 7 राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को संबंधित राज्यों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श और प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता, राज्यों के हिस्से और लाभार्थियों के बारे में संतुष्ट होने के बाद मंजूरी दी। स्वीकृत किये गये मकान इन 7 राज्यों के 163 शहरों में बनाए जाएंगे। सरकार की 'सबके लिए आवास' पहल के अंतर्गत कुल स्वीकृत मकानों में से 58,456 मकान 'लाभार्थी की अगुवाई में निर्माण' संघटक के अंतर्गत बनाए जाएंगे। इसके अंतर्गत लाभार्थी अपनी जमीन पर केन्द्र और राज्य सरकारों की सहायता से नये मकान बनवाएंगे। 'भागीदारी के साथ किफायती मकान' संघटक के अंतर्गत

केन्द्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 4,976 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 7 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 86,179 मकानों का निर्माण करने को 18 फरवरी को मंजूरी प्रदान की। इसके लिए, मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत शहरों में रहने वाले गरीबों को लाभांशित करने के लिए 1.50 लाख रुपये प्रति मकान की दर से कुल 1,226 करोड़ रुपये की कुल केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा।

23,301 अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे, जिसके तहत राज्य सरकारें जमीन उपलब्ध कराएंगी और केन्द्र सरकार प्रति लाभार्थी 1.50 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी। पश्चिम बंगाल के लिए 38 शहरों में कुल 27,830, तेलंगाना के लिए 45 शहरों में 22,817, बिहार के लिए 40 शहरों में 13,315, मिजोरम के लिए 6 शहरों में 8,922, राजस्थान में 9 शहरों के लिए 6,052, झारखंड के लिए 24 शहरों में 2,337 और उत्तराखंड के लिए देहरादून में 484 मकानों को मंजूरी दी गई है।

प्रमुख शहरों के लिए निम्नलिखित मकानों को मंजूरी प्रदान की गई है:

पश्चिम बंगाल: हल्दिया-1626, हावड़ा-1621, बदुरिया-1607, बारासात-1592, राजपुर सोनपुर-1334,

मेदनीपुर-1332, बशीरहाट-1012, झारग्राम-1042, संतीपुर-1006 और क्रुर्सियांग -164.

बिहार: भागलपुर-709, बिहार शरीफ-396, छपरा-562, हाजीपुर-304, खगरिया-500, महाराजगंज-808, सिहोर-550, सीतामढ़ी-500, सुल्तानगंज-150, झाजपुर-500, किशनगंज-458 और सहरसा-1000.

राजस्थान: कैथुन (कोटा)-912, जहाजपुर-888, झालावाड़-744, केसोरीयापाटन-760, लाखीरी-688, चाक्सु -608, भीलवाड़ा-604, कापरेन-320, डुंगरपुर-272 और शिवगंज-256.

झारखंड: पाकोर-215, विश्रामपुर-178, बुंदू-102, गढ़वा-199, जामताड़ा-132, खूंटी-167, कोडरमा-100, मधुपुर-225.

मिजोरम: लंगलई-2450, चामफेई-2417, सइहा-1590, कोलासिब-890, सरचिप-1013 और मामित -562.

गौरतलब है कि इस अनुमोदन के साथ सरकार अब तक 13 राज्यों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 7,519 करोड़ रुपये की कुल केन्द्रीय सहायता के साथ कुल 5.07 लाख मकानों को मंजूरी दे चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, सरकार ने देश में 4,041 संवैधानिक शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए 2 करोड़ मकानों के निर्माण में सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ■

प्रधानमंत्री ने किया फसल बीमा योजना के लिए संचालनगत दिशा-निर्देशों का अनावरण

राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का होगा अम्बेडकर जयंती पर शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 फरवरी को मध्य प्रदेश के सीहोर में किसानों की एक विशाल रैली में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए संचालनगत दिशा-निर्देशों का अनावरण किया। किसानों के लिए इस व्यापक फसल बीमा योजना के लाभों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा

गन्ना किसानों के बकाये को खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया, जो कई हजार करोड़ रुपये तक पहुंच चुका था। 'डिजिटल इंडिया' अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा किसानों का कल्याण इस पहल के मूल में है। उन्होंने 14 अप्रैल 2016, बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर

को बीमा दावों के निपटान प्रमाण पत्र भी प्रदान किए।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि दस साल पहले हिन्दुस्तान के कृषि के नक्शे पर मध्य प्रदेश का नामो-निशान नहीं था। कृषि क्षेत्र में योगदान करने वाले राज्यों में पंजाब, हरियाणा, गंगा-यमुना के तट या कृष्ण-गोदावरी के तट, यही इलाके हिन्दुस्तान में कृषि क्षेत्र के इलाके माने जाते थे, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों ने अपनी सूझबूझ से, अपने परिश्रम से, नए-नए प्रयोगों से और मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने अनेक वित्त किसान लक्ष्य योजनाओं के रहते, ग्रामीण विकास की योजनाओं के रहते और किसान की जो मूलभूत आवश्यकता है, उस पानी पर बल देने के कारण राज्य सरकार और किसानों ने मिलकर के एक नया इतिहास रचा है और आज हिन्दुस्तान के कृषि जगत में मध्य प्रदेश सिरमौर बन गया है।



कि यह परेशानियों के वक्त किसानों की समस्याओं के लिए एक समाधान मुहैया करा सकता है। उन्होंने कहा कि पुरानी फसल बीमा योजनाओं की कमियों को दूर करने तथा फसल बीमा को लेकर किसानों के बीच भरोसा कायम करने का पूरा प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए इस योजना में व्यापक रूप से प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

प्रधानमंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाई कई अन्य पहलों को रेखांकित किया। उन्होंने

डिजिटल प्लेटफॉर्म-राष्ट्रीय कृषि बाजार को लांच करने की घोषणा की। यह किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य दिलाने में सक्षम होगा।

प्रधानमंत्री ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जैव खेती और यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने जैसे कृषि क्षेत्र में उठाए गए अन्य बड़े कदमों का भी जिक्र किया। श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि क्षेत्र में राज्य के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं चुने हुए लाभार्थियों

उन्होंने कहा कि चार-चार साल लगातार, कृषि क्षेत्र का अवॉर्ड एक राज्य जीतता चला जाए, यह छोटी बात नहीं है और उनकी वृद्धि भी देखिए। कभी जीरो पर से दस पर पहुंचना सरल होता है, लेकिन 15-17-18 पर से 20-22 या 24 पर पहुंचना बहुत कठिन होता है। जो लोग कृषि अर्थशास्त्र को समझते हैं, वो भली-भांति जान सकते हैं कि भारत की आर्थिक विकास की यात्रा में मध्य प्रदेश के कृषि जगत का कितना बड़ा योगदान है। इसलिए मैं

विशेष रूप से आज यहां आकर के लाखों किसानों की हाजिरी में 'कृषि कर्मण अवॉर्ड' दे रहा हूं। यह अवॉर्ड तो मैंने मुख्यमंत्री के हाथ में दिया, राज्य के कृषि मंत्री के हाथ में दिया, लेकिन हकीकत में तो यह जो 'कृषि कर्मण अवॉर्ड' है, वो मैं मध्य प्रदेश के कोटि-कोटि लाखों मेरे किसान भाइयों-बहनों को देते हुए कोटि-कोटि वंदन करता हूं।

श्री मोदी ने कहा कि संपूर्ण देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके दिशा-निर्देश आज मध्य प्रदेश के किसानों की हाजिरी में समग्र देश के किसानों को अर्पित की जा रही है। इसका हक मध्य प्रदेश के किसानों का बनता है जिन्होंने एक नया इतिहास रचा है और इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आरंभ भी मध्य प्रदेश से करना बहुत ही उचित मुझे लगता है और उसके कारण आज इस कार्यक्रम की रचना की गई।

उन्होंने कहा कि एक समय था कि किसान फसल बीमा कुछ इलाकों में तो 14 प्रतिशत तक जाना पड़ा। कुछ इलाकों में 6 प्रतिशत-8 प्रतिशत गया। बीमा कंपनियां तय करती थी, मजबूरी का फायदा उठाती थी। इस सरकार ने निर्णय कर लिया कि हम जब बीमा योजना करेंगे, तो रबी फसल के लिए डेढ़ प्रतिशत से ज्यादा किसान से प्रीमियम नहीं लिया जाएगा और खरीफ में 2 प्रतिशत से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। कहां 12-14 प्रतिशत तक लूटा जाता था और कहां 2 प्रतिशत का कैप लगा दिया। उन्होंने क्या किया था? भुगतान के ऊपर कैप लगा दी थी, एक दीवार लगा दी थी कि इससे ज्यादा भुगतान नहीं होगा। हमने प्रीमियम पर तो कैप लगा दी,

लेकिन किसान को जब मिलने की नौबत आएगी, उस पर कोई कैप नहीं रहेगी। जितना बीमा वो कराएगा, उतना ही पैसा उसका हक बनेगा और उसको देने का काम होगा। यह बहुत बड़ा निर्णय है।

श्री मोदी ने कहा कि पहले बीमा लेते थे तो बीमा मंजूर होने में चार-चार सीजन चले जाते थे, निर्णय नहीं होता था, बीमा कंपनी, सरकार और किसान के बीच कागज ही चलते रहते थे। हमने निर्णय किया है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, तत्काल सर्वे करने में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा और 25 प्रतिशत राशि उसको तत्काल दी जाएगी और बाद की प्रक्रिया कम से कम समय में पूर्ण करके किसान को दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि आज 20 प्रतिशत से ज्यादा लोग बीमा नहीं लेते। क्या हिन्दुस्तान के 50 प्रतिशत किसान बीमा योजना में जुड़ने को, आगे आने को तैयार हैं? जितने ज्यादा किसान जुड़ेंगे, इतना सरकार की तिजोरी पर बोझ बढ़ने वाला है। जितने ज्यादा किसान बीमा लेंगे, सरकार की तिजोरी से उतना पैसा ज्यादा जाने वाला है। उसके बावजूद भी मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि आप इस बीमा योजना के साथ जुड़िए। हिन्दुस्तान में पहली बार किसानों की भलाई के लिए इतनी बड़ी योजना लाई गई है और एक बार किसान इस योजना से जुड़ गया तो आने वाले दिनों में प्राकृतिक संकट किसान को कभी डुला नहीं पाएंगे,

हिला नहीं पाएंगे, डरा नहीं पाएंगे, सरकार उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी रहेगी।

श्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में कोई वर्ष ऐसा नहीं होता है कि जब देश के किसी न किसी इलाके में प्राकृतिक आपदा न आई हो और किसानों को भयंकर नुकसान होता है। किसी न किसी इलाके में होता ही होता है, लेकिन पहले नियम ऐसे थे कि अगर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आगामी खरीफ सीजन से लागू हो जाएगी। इस योजना के तहत खरीफ की फसलों के लिए किसानों को सिर्फ दो प्रतिशत प्रीमियम चुकाना होगा। यह व्यवस्था समान रूप से लागू की जा रही है। रबी फसल के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा। वार्षिक कारोबारी और बागवानी फसलों के लिए यह प्रीमियम 5 प्रतिशत होगा। इस योजना के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। प्रीमियम दर के सीमांकन का प्रावधान पहले की योजनाओं में था, लेकिन किसानों को इसके लिए काफी कम पैसे मिलते थे। अब किसान बिना किसी कटौती के समूची फसल की बीमा के एवज में दावे प्राप्त कर पाएंगे।

उस इलाके में 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ होगा, तब जाकर के सरकार वहां पर हिसाब-किताब शुरू करेगी। हमने इस निर्णय को बदल दिया और हमने कहा कि 50 प्रतिशत नहीं, एक-तिहाई भी अगर नुकसान हुआ है तो भी किसान को इस नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा।

यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय किया गया है। पहले किसान को जो मुआवजा दिया जाता था, इसको करीब-करीब तीन गुना कर दिया गया है।■

प्रधानमंत्री ने किया राष्ट्रीय रूरुर्बन मिशन का शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 फरवरी को छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव जिले के कुरुभात नामक स्थान से राष्ट्रीय रूरुर्बन मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रूरुर्बन मिशन 'ग्रामीण आत्मा और शहरी सुविधाओं' से युक्त कलस्टर आधारित विकास करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि यह योजना स्मार्ट गांवों का निर्माण करके स्मार्ट शहरों की पहल की पूरक बनेगी। उन्होंने रूरुर्बन कलस्टरों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बताया जो विकास को प्रोत्साहित करेंगे और आसपास के गांव में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसका एक उदाहरण यह है कि यह महत्वपूर्ण रूरुर्बन मिशन नई दिल्ली से शुरू न होकर छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव जिले में कुरुभात से शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को अब गांव और आदिवासी समुदायों के दरवाजे पर लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करने के लिए आस-पास के इलाके के गांवों और समुदायों को बधाई दी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने इसी स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी का दौरा किया जिसमें विकास योजनाओं और हस्तशिल्प के कार्यान्वयन को प्रदर्शित किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना घर बनाने में असमर्थ लोगों को सहायता प्रदान करेगी: मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माण होने वाली आवासीय

योजना की आधारशिला का शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग कलस्टर की आधारशिला का अनावरण किया और छत्तीसगढ़ की नवाचार और उद्यमिता विकास नीति का विमोचन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि



प्रधानमंत्री आवास योजना घर बनाने में असमर्थ लोगों को सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नवाचार और उद्यमिता विकास नीति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना की और कहा कि विगत पचास वर्ष में नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने वाले देशों को सफलता प्राप्त हुई है और इन देशों में आर्थिक समृद्धि देखी गई है।

उन्होंने केंद्र सरकार की कौशल विकास और मुद्रा योजनाओं के संबंध में भी जानकारी दी। इससे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोदी ने श्री सत्य साई बाबा की मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने मानव संसाधन विकास केंद्र-श्री सत्य साई सौभाग्यम का शुभारंभ किया और मानवता की सेवा के लिए श्री सत्य साई संजीवनी

शिशु स्वास्थ्य देखभाल केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया।

भारत की आध्यात्मिक जागृति बरकरार: मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 फरवरी को कोलकाता में गोड़िया मिशन और मठ के शत वार्षिकी समारोह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत

की आध्यात्मिक जागृति के पीछे इसकी सभ्यता का पुराना चरित्र है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भारत की यह आध्यात्मिक जागृति बरकरार है। उन्होंने कहा यह आध्यात्मिक जागृति, चेतना या विवेक भाषा तक भी पहुंच जाता है। 'वैष्णव जन तो तेने रे कहिये' इसका एक प्रमुख उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि आधुनिक संदर्भ में वैष्णव जन शब्द की जगह आसानी से जन प्रतिनिधि शब्द को रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय समाज में सुधार हमेशा अंदर से हुआ है। राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री बाद में गोड़िया मठ की प्रार्थना में भी शामिल हुए। ■

जनवरी, 2016 के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन में 6.8 फीसदी का इजाफा पर्यटक आगमन में सर्वाधिक हिस्सा अमेरिका का रहा

केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय के अनुसार जनवरी, 2016 के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन में 6.8 फीसदी का इजाफा हुआ, जो एक उपलब्धि है। विदेशी पर्यटकों के आगमन से देश को न केवल बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, बल्कि देश के अंतर्गत रोजगार के तमाम अवसर उत्पन्न होते हैं। खास बात यह है कि पर्यटकों के आगमन से स्थानीय स्तर पर सामान्य जनों को बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे लोगों का बड़े शहरों की तरफ पलायन कम होता है। दरअसल, पर्यटन मंत्रालय आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) से प्राप्त राष्ट्रीयता-वार एवं बंदरगाह-वार आंकड़ों के आधार पर विदेशी पर्यटकों के आगमन (एफटीए) के मासिक अनुमानों का संकलन करता है। इसी तरह पर्यटन मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पर्यटन से प्राप्त विदेशी मुद्रा आमदनी (एफईई) का संकलन करता है। जनवरी, 2016 के दौरान एफटीए और एफईई से जुड़ी खास बातें निम्नलिखित रहीं:

विदेशी पर्यटकों का आगमन (एफटीए)

जनवरी, 2016 के दौरान एफटीए का आंकड़ा 8.44 लाख का रहा, जबकि जनवरी 2015 में यह 7.91 लाख और जनवरी 2014 में 7.58 लाख था। जनवरी, 2015 की तुलना में जनवरी 2016 के दौरान इसमें 6.8 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

शीर्ष 15 स्रोत देशों में जनवरी, 2016 के दौरान भारत में एफटीए में

जनवरी, 2016 के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन में 6.8 फीसदी का इजाफा हुआ, जो एक उपलब्धि है। विदेशी पर्यटकों के आगमन से देश को न केवल बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, बल्कि देश के अंतर्गत रोजगार के तमाम अवसर उत्पन्न होते हैं।

सर्वाधिक हिस्सा अमेरिका (15.29 फीसदी) का रहा। इसके बाद हिस्सा क्रमशः बांग्लादेश (11.99 प्रतिशत), ब्रिटेन (11.23 प्रतिशत), कनाडा (4.87 प्रतिशत), ऑस्ट्रेलिया (3.97 प्रतिशत), रूसी संघ (3.71 प्रतिशत), जर्मनी (3.27 प्रतिशत), फ्रांस (2.98 प्रतिशत), श्रीलंका (2.97 प्रतिशत), चीन (2.74 प्रतिशत), मलेशिया (2.59 प्रतिशत), जापान (2.38 प्रतिशत), कोरिया गणराज्य (1.82 प्रतिशत), नेपाल (1.76 प्रतिशत) और अफगानिस्तान (1.62 प्रतिशत) का रहा।

शीर्ष 15 पोर्टों में जनवरी, 2016 के दौरान एफटीए में सर्वाधिक हिस्सा दिल्ली एयरपोर्ट (28.38 फीसदी) का रहा। इसके बाद हिस्सा क्रमशः प्रतिशत मुंबई एयरपोर्ट (19.59 प्रतिशत), चेन्नई एयरपोर्ट (7.92 प्रतिशत), हरिदासपुर लैंड चेक पोस्ट (6.58 प्रतिशत), बेंगलुरु एयरपोर्ट (5.72 प्रतिशत), गोवा एयरपोर्ट (5.68 प्रतिशत), कोलकाता एयरपोर्ट

(3.92 प्रतिशत), कोच्चि एयरपोर्ट (3.86 प्रतिशत), अहमदाबाद एयरपोर्ट (3.48 प्रतिशत), हैदराबाद एयरपोर्ट (2.83 प्रतिशत), तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट 1.84 प्रतिशत), गेडे रेल (1.51 प्रतिशत), तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट (1.26 प्रतिशत), अमृतसर एयरपोर्ट (0.82 प्रतिशत) और सोनौली लैंड चेक पोस्ट (0.76 प्रतिशत) का रहा।

रुपए व डॉलर के लिहाज से भारत में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आमदनी (एफईई) जनवरी 2016 के दौरान 13,669 करोड़ रुपए की रही, जबकि यह जनवरी 2015 में 12,100 करोड़ रुपए और जनवरी 2014 में 11,664 करोड़ रुपए थी। जनवरी 2016 के दौरान रुपए के लिहाज से एफईई की वृद्धि दर जनवरी 2015 के मुकाबले 13.0 फीसदी रही, जबकि जनवरी 2014 के मुकाबले जनवरी, 2015 में वृद्धि दर 3.7 फीसदी आंकी गई थी।

जनवरी, 2015 की तुलना में जनवरी, 2016 के दौरान अमेरिकी डॉलर के लिहाज से एफईई 2.032 अरब अमेरिकी डॉलर की रही। जनवरी 2015 में एफईई 1.945 अरब अमेरिकी डॉलर और जनवरी 2014 में 1.880 अरब अमेरिकी डॉलर दर्ज की गई थी। जनवरी, 2016 के दौरान अमेरिकी डॉलर के लिहाज से एफईई की वृद्धि दर जनवरी 2015 के मुकाबले 4.5 फीसदी रही, जबकि जनवरी 2014 के मुकाबले जनवरी 2015 में यह वृद्धि दर 3.5 फीसदी आंकी गई थी। ■

आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने अतिरिक्त रेल लाइनों के निर्माण को मंजूरी दी कई रूट पर बिछेंगे दोहरे ट्रैक, माल दुलाई को बनेंगे गलियारे

रेलवे कई इलाकों में अपनी लाइनों को डबल और ट्रिपल ट्रैक बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा माल दुलाई के लिये चार विशेष गलियारों का भी निर्माण किया जायेगा। ट्रैक बढ़ाने वाली नौ सौ किलोमीटर से अधिक की इन परियोजनाओं की लागत 10,700 करोड़ रुपये से ज्यादा होगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 17 फरवरी को देश के विभिन्न हिस्सों में यात्री एवं माल दुलाई दोनों की ही बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए छह रेल लाइनों और एक रेल पुल के निर्माण को मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों पर 10,700 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की लागत आएगी और कुल खर्च के अधिकांश हिस्से को अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने बताया कि इनमें कई परियोजनायें कोयला खनन क्षेत्रों में हैं। इनके पूरा होने से कोयला दुलाई में तेजी आयेगी। इन 6 मंजूर परियोजनाओं का विवरण निम्न है।

रेलवे को मिली नई गति

आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर परियोजनाओं के अंतर्गत कर्नाटक में हुबली-चिकाजूर रेलवे लाइन (190 किलोमीटर) का डबल ट्रैक, महाराष्ट्र के वर्धा सेवाग्राम से तेलंगाना के बल्हारशाह के बीच रेलवे खंड (132 किलोमीटर) में ट्रिपल ट्रैक, झारखंड के रमना से मध्यप्रदेश के सिंगरौली तक रेललाइन (160 किलोमीटर) में डबल ट्रैक, मध्यप्रदेश में अनूपपुर-कटनी रेल खंड (165

आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर परियोजनाओं के अंतर्गत कर्नाटक में हुबली-चिकाजूर रेलवे लाइन (190 किलोमीटर) का डबल ट्रैक, महाराष्ट्र के वर्धा सेवाग्राम से तेलंगाना के बल्हारशाह के बीच रेलवे खंड (132 किलोमीटर) में ट्रिपल ट्रैक, झारखंड के रमना से मध्यप्रदेश के सिंगरौली तक रेललाइन (160 किलोमीटर) में डबल ट्रैक, मध्यप्रदेश में अनूपपुर-कटनी रेल खंड (165 किलोमीटर) में ट्रिपल ट्रैक, मध्यप्रदेश में ही कटनी-सिंगरौली रेललाइन (261 किलोमीटर) में डबल ट्रैक शामिल है। इन्हीं परियोजनाओं में बिहार में पटना-बेगूसराय को जोड़ने वाले राजेन्द्र पुल का अतिरिक्त पुल निर्माण भी शामिल है।

किलोमीटर) में ट्रिपल ट्रैक, मध्यप्रदेश में ही कटनी-सिंगरौली रेललाइन (261 किलोमीटर) में डबल ट्रैक शामिल है। इन्हीं परियोजनाओं में बिहार में पटना-बेगूसराय को जोड़ने वाले राजेन्द्र पुल

का अतिरिक्त पुल निर्माण भी शामिल है।

हुबली-चीकाजूर रेल लाइन का दोहरीकरण

190 किलोमीटर लंबी हुबली-चीकाजूर ब्रॉड गेज एकल रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है। इस पर कुल मिलाकर 1294.13 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। यह परियोजना 13वीं योजनावधि के दौरान सवा चार वर्षों में पूरी होने की संभावना है और यह चित्रदुर्ग, दावणगेरे, हावेरी एवं धारवाड़ क्षेत्रों को कवर करेगी। दोहरीकरण के लिए पुणे-मिराज-हुबली-बेंगलुरु के समूचे रूट की पहचान की गई है, जिससे न केवल यातायात के प्रवाह में और ज्यादा सुगमता आएगी, बल्कि इस क्षेत्र के समग्र विकास को भी नई गति मिलेगी।

यह खंड मुंबई एवं बेंगलुरु के बीच यात्री रेलगाड़ियों और मंगलोर स्थित बंदरगाहों तक जाने वाली मालगाड़ियों के एक महत्वपूर्ण रेल संपर्क का हिस्सा है। इस रूट पर बेंगलूर-टुमकुर और अर्सिकेरे-चीकाजूर के दोहरीकरण का काम पहले ही पूरा कर लिया गया है। शेष हिस्से में हुबली-लोंडा-वास्को-डा-गामा के

हुबली-लॉन्डा भाग के दोहरीकरण का काम भी जारी है।

वर्धा (सेवाग्राम)-बल्लारशाह तीसरी रेल लाइन का निर्माण

132 किलोमीटर लंबी वर्धा (सेवाग्राम)-बल्लारशाह तीसरी रेल लाइन का निर्माण कार्य 1443.32 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ शुरू किया जाएगा। यह परियोजना 13वीं योजनावधि के दौरान पांच वर्षों में पूरी होने की संभावना है और यह वर्धा एवं चंद्रपुर जिलों में अवस्थित होगी। इस खंड की लाइन क्षमता का उपयोग अपनी पूर्णता पर पहुंच चुका है और इस खंड पर अतिरिक्त मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों एवं मालगाड़ियों की आवाजाही से ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है।

वर्धा (सेवाग्राम)-बल्लारशाह खंड नागपुर प्रभाग से आने वाली वस्तुओं के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां इस खंड पर अनेक कोयला खदानें और कई छोटी पटरियां प्रस्तावित हैं।

रमना-सिंगरौली रेल लाइन का दोहरीकरण

160 किलोमीटर लंबी रमना-सिंगरौली रेल लाइन के दोहरीकरण को 2675.64 करोड़ रुपये की लागत के साथ मंजूरी दी गई है और यह परियोजना वर्ष 2019-20 तक पूरी होने की संभावना है। यह परियोजना झारखंड के गढ़वा, मध्य प्रदेश के सिंगरौली और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिलों को कवर करेगी।

रमना-सिंगरौली खंड पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद प्रभाग में पड़ता है। मौजूदा समय में इस खंड का यातायात उपयोग 105 फीसदी है, जिससे रेलगाड़ियों का परिचालन बाधित होता

है और इसके साथ ही राजस्व का नुकसान भी होता है। इस खंड पर अपेक्षित यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने और इस खंड की क्षमता बढ़ाने के लिए एकल लाइन वाले इस खंड का दोहरीकरण परिचालन की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है।

अनूपपुर और कटनी के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण

मध्य प्रदेश में अनूपपुर और कटनी के बीच 165 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन के निर्माण को भी 1595.76 करोड़ रुपये की लागत के साथ मंजूरी दी गई है। यह परियोजना 12वीं एवं 13वीं योजनावधि के दौरान सवा पांच वर्षों में पूरी होने की संभावना है।

यह परियोजना मध्य प्रदेश के अनूपपुर, शहडोल, उमरिया एवं कटनी जिलों को कवर करेगी। हाल के महीनों में कोयले एवं अयस्क के खनन में भारी वृद्धि देखने को मिली है तथा इन संसाधनों के दोहन की दिशा में आने वाले वर्षों में और आगे बढ़ने के लिए बनाई गई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर अब तक अमल नहीं हो पाया है। तेजी से हुए औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप परियोजना लाइन के आसपास अनेक औद्योगिक टाउनशिप भी विकसित हो गई है। इन बदलावों से इस खंड पर अतिरिक्त कोचों के लिए भारी मांग की जा रही है।

कटनी-सिंगरौली रेल लाइन का दोहरीकरण

261 किलोमीटर लंबी कटनी-सिंगरौली रेल लाइन के दोहरीकरण को 2084.90 करोड़ रुपये की लागत के साथ मंजूरी दी गई है। यह परियोजना सवा पांच वर्षों में पूरी होगी। यह परियोजना मध्य प्रदेश में

कटनी, शहडोल, सिद्धि और सिंगरौली जिलों को कवर करेगी।

अतिरिक्त पुल का निर्माण और रामपुर डुमरा-ताल-राजेन्द्रपुल की दोहरीकरण परियोजना

बिहार में अतिरिक्त पुल के निर्माण और रामपुर डुमरा-ताल-राजेन्द्रपुल खंड की दोहरीकरण परियोजना को भी सीसीईए ने 1700.24 करोड़ रुपये की लागत के साथ मंजूरी दे दी। यह परियोजना वर्ष 2019-20 तक पूरी होने की संभावना है। यह परियोजना बिहार के बेगूसराय और पटना जिलों में अवस्थित है।

हाथीदा में मौजूदा रेल-सह-सड़क पुल पर एकल लाइन वाला ट्रैक है और दोहरीकरण संभव नहीं है। इस खंड का क्षमता उपयोग मौजूदा समय में 123.5 फीसदी है। वर्तमान में यही एकमात्र रेल पुल है जो उत्तरी एवं दक्षिणी बिहार को एक-दूसरे से जोड़ता है।

एकल लाइन वाले इस खंड पर परिचालन को दुरुस्त करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि एक अतिरिक्त पुल और इस खंड के दोहरीकरण का काम शुरू किया जाए। यह सुविधा हासिल हो जाने से इस खंड पर रेलगाड़ियों के परिचालन को बरकरार रखने के साथ-साथ और ज्यादा यात्री ट्रेनों/मालगाड़ियों को चलाने के लिए भी पर्याप्त गुंजाइश निकल आएगी।

इससे लाइन क्षमता में भी काफी वृद्धि होगी। इसके अलावा, इससे किऊल-बरौनी और मोकामा-बरौनी खंड पर रेलगाड़ियों के परिचालन समय को न्यूनतम रखने में भी मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, इससे इस खंड पर परिचालन की मौजूदा बाधाओं को दूर करने में भी मदद मिलेगी। ■